जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक:201 दिनांक:26-11-2024 मंगलवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। लोकसभा में विपक्ष अडाणी मामले पर हंगामा करता रहा।

भारतीय तट रक्षक ने अंडमान सागर में एक मछली पकड़ने वाली नाव से लगभग 6 टन ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की है। यह बरामदगी भारतीय तट रक्षक द्वारा अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप हो सकती है।

संसद का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा

-अब 27 नवंबर को होगी सदन की कार्यवाही

नई दिल्ली(ईएमएस)। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही यह विपक्ष के हंगामें की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत कई अन्य विपक्षी दलों ने संभल में मारे गए मुस्लिम उपद्रवियों के लिए कथित न्याय की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने तो अडानी को लेकर हंगामा खड़ा करने की कोशिशें की। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा को पहले एक घंटे और फिर 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

संसदीय प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा करने पर अड़ा हुआ था। हालांकि, स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के चलते सदन को ही स्थगित कर दिया।

शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने हैं 16 बिल

गौरतलब है कि 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र को 20 दिसंबर तक चलना है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि बिलों को पास कराने में सरकार को खासी मशक्कत करने पड़ेगी। सरकार के पास 25 दिनों का समय शेष है और इतने ही दिनों में 16 विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाना है।

जिन बिलों सदन में पेश किया जाना है उनमें

संसद के सत्र के दौरान 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, बॉयलर्स बिल, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय बिल, पंजाब न्यायालय (संशोधन) बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, तटीय शिपिंग बिल और भारतीय बंदरगाह बिल सूची में शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए फिजिकल क्लासेस शुरु करने पर विचार करें

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के तहत स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों की फिजिकल कक्षा पर लगी पाबंदियों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया। ये पाबंदियां पिछले हफ्ते खतरनाक हवा को देखकर लगाई गई थीं। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इसका आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि बहुत सारे छात्र फिजिकल कक्षा बंद होने के कारण मिड-डे मील का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं, इसलिए इसतरह के घरों में बाहर और अंदर की हवा में ज्यादा फर्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएमक्यूएम 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए फिजिकल क्लासेस जारी रखने पर भी फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीएमक्यूएम कल तक इस बारे में फैसला ले।

सुनवाई में अदालत ने सीएमक्यूएम से कहा, 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी फिजिकल क्लासेस शुरू करने पर विचार करे। क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्कूल जाना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीएमक्यूएम को बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों बातों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए।

अंडमान के पास 6 हजार किलो ड्रग्स जब्त

म्यांमार की बोट में 2-2 किलो के 3 हजार पैकेट मिले, कोस्टगार्ड की सबसे बड़ी जब्ती

नई दिल्ली (ईएमएस)। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान-निकोबार आइलैंड के पास से 6 हजार किलो की ड्रग्स जब्त की है। कोस्ट गार्ड के अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पोर्ट ब्लेयर से 150 किलो मीटर दूर बैरेन आइलैंड के पास एक नाव से ड्रग्स के 2-2 किलो के 3 हजार पैकेट मिले। नाव में म्यांमार के 6 नागरिक सवार थे। सभी को हिरासत में लिया गया है।

कोस्टगार्ड के अधिकारी ने बताया कि 24 नवंबर को कोस्टगार्ड के डोर्नियर एयरक्राफ्ट के रूटीन पैट्रोलिंग के दौरान पायलट को यह बोट दिखाई दी थी। ड्रग्स स्मगलिंग का शक होने पर पायलट ने बोट के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोट की रफ्तार बढ़ा दी और भागने की कोशिश करने लगे। पायलट ने पोर्ट ब्लेयर पुलिस को सूचित किया। कुछ देर बाद पुलिस और कोस्टगार्ड ने मिलकर बोट को पकड़ लिया। जब बोट से तलाशी ली गई तो उसमें करोड़ों रुपए की ड्रग्स मिली। इसकी भारत में तस्करी होनी थी। यह अब तक की सबसे बड़ी खेप थी, जो कोस्टगार्ड ने पकड़ी हो।

सीएनजी के दाम 4 रुपए प्रति किलो तक बढ़े

- एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में सीएनजी की कीमत बढ़ी

नई दिल्ली (ईएमएस)। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। सीएनजी की कीमतों में 1.5 रुपये से 4 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी की घोषणा कंपनी ने की है। आईजीएल ने इस मूल्य वृद्धि से दिल्ली को दूर रखा है, वहीं एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में सीएनजी की कीमत में इजाफा किया है। कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से आईजीएल के ऑपरेशन वाले लगभग 30 फीसदी क्षेत्रों पर असर पड़ने की उम्मीद है। कंपनी की कुल सीएनजी खपत का 70 फीसदी हिस्सा दिल्ली से आता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, करनाल और कैथल में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमंद में 1.5 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, महोबा, बांदा और चित्रकूट में आईजीएल ने सीएनती का भाव 3 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाया है। मुंबई में पहले ही सीएनजी की कीमतें बढ़ चुकी हैं। महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने मुंबई में सीएनजी की कीमतें 2 रुपये प्रतिकिलोग्राम बढ़ाकर 75 रुपये प्रति किलो से 77 रुपये कर दिया है। आईजीएल और एमजीएल ने सीएनजी के भाव सरकार के 16 नवंबर से पुरानी गैस फील्ड से मिलने वाली सस्ती प्राकृतिक गैस की सप्लाई में 20 फीसदी की कटौती करने के बाद की है। इससे पहले 16 अक्टूबर को भी सप्लाई में 21 फीसदी की कटौती की गई थी। इन कटौतियों के बाद आईजीएल, एमजीएल और अडानी टोटल गैस जैसी गैस कंपनियों ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ने की आशंका जताई थी।

संविधान की प्रस्तावना से नहीं हटेंगे धर्म निरपेक्ष और समाजवाद

सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से धर्म निरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन अमान्य नहीं हो सकता। 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन के जरिये प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में दाखिल याचिका पर विस्तार से सुनवाई की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लार्जर बेंच रेफर करने से इनकार कर दिया था और मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सीजेआई की बेंच ने कहा कि धर्म निरपेक्ष और समाजवाद शब्द संविधान में 1976 में किए गए संशोधन के तहत जोड़े गए थे और इसे 1949 से लागू कर दिया गया था, लेकिन इससे इसकी वैधता प्रभावित नहीं होती है। 1949 यानी पहले के प्रभाव से लागू होने से तथ्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अदालत ने कहा कि संसद को संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने का अधिकार है और संशोधन की वैधता पर अब सवाल नहीं उठाए जा सकते। संसद को संविधान में संशोधन का जो अधिकार मिला हुआ है, वह प्रस्तावना पर भी लागू होता है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अलग नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संदर्भ में सोशलिस्ट का अर्थ वेलफेयर ऑफ स्टेट से है। भारत में समाजवाद का मतलब अलग संदर्भ में है। यह राज्य को लोगों के वेलफेयर और समान अवसर प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। सेक्युलर शब्द के बारे में उन्होंने कहा कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। यह बात एसआर बोम्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है।

आपातकाल में किया गया संशोधन वैध नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकर्ताओं ने दलील दी कि यह संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान हुआ था तब लोगों को इस मामले में पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। साथ ही यह मूल ढांचा में बदलाव था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार सिर्फ संविधान सभा को था। साथ ही इस संसोधन को राज्यों से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था कि संशोधन प्रक्रिया पर आपातकाल की परिस्थितियों का असर नहीं पड़ता और इस दौरान किए गए संसद के निर्णय को अमान्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द संविधान के उद्देश्यों के अनुसार हैं।

यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ इलाबाबाद हाईकोर्ट ने मिल्कीपुर से जुड़ी याचिका वापसी की

लखनऊ (ईएमएस) । यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इलाबाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस पंकज भाटिया ने मिल्कीपुर से जुड़ी याचिका वापसी की अर्जी स्वीकार कर ली है। पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने 2022 में मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि अवधेश प्रसाद के नामांकन पत्रों में विसंगतियां हैं। लेकिन, याचिका वापस लेने के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में उपचुनाव कराए जा सकते हैं।

गोरखनाथ और निर्दलीय उम्मीदवार राम मूरत ने 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई थी। इसमें कहा गया था कि अब यह केस नहीं लड़ना चाहते हैं। हाईकोर्ट ऑर्डर की कॉपी अब चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखों पर फैसला लेगा।

सपा के अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे। उन्होंने फैजाबाद सीट से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। उन्होंने 7 हजार वोटों से जीत हासिल की थी। इसके बाद ये सीट खाली हो गई थी।

दरअसल, साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। उन्होंने विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए थे और उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। गोरखनाथ की तरफ से कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई है, जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। ऐसे में यह हलफनामा अवैध था। गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी।

अमित शाह से मुलाकात करने देवेंद्र फडणवीस पहुंचे दिल्ली

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ऐलान जल्द

मुंबई (ईएमएस)। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान 26 नवंबर तक हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच चुक हैं। सूत्रों के अनुसार, वह रात करीब 11 बजे अमित शाह से मिलेंगे। इसके बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों का दावा है मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। एक मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री का फॉर्मूला नई सरकार पर भी लागू रहेगा। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। इस हिसाब से भाजपा के 22-24, शिंदे गुट के10-12 और अजित गुट के 8-10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। राज्य में 26 नवंबर तक सरकार का गठन होना है। इसकी वजह ये है कि विधानसभा का कार्यकाल इस दिन खत्म हो रहा है, सरकार गठित न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा।

आदित्य ठाकरे बने विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के नेता

दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हुई बैठक में आदित्य ठाकरे को विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में पार्टी का संयुक्त नेता चुना गया है। भास्कर जाधव को शिवसेना (यूबीटी) के विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप चुना गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि पार्टी ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव में नाना पटोले ने ही कांग्रेस की टिकट बांटी थीं। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं। पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 16.1 फीसदी था, जो अब घटकर 12.42 फीसदी रह गया है।

महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए भाजपा-शिंदे सेना में फंसा पेंच, लग सकता है राष्ट्रपति शासन ?

मुंबई (ईएमएस) । महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद महायुति सरकार के सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। 26 नवंबर को सीएम पद का फैसला नहीं हुआ तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।

भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिलने से सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है। सवाल ये है कि सीएम की कुर्सी पर फडणवीस को बैठाने का फैसला एकनाथ शिंदे को मंजूर होगा? अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर शिंदे क्या करेंगे? वो केंद्र में जाएंगे या डिप्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे?

132 सीटें मिलने से BJP का तो दावा मजबूत हुआ है, लेकिन शिंदे की शिवसेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नतीजतन चुनाव नतीजे आने के दो दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के सांसद नरेश म्हस्के ने कहा, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि लाड़की बहिन योजना का आइडिया उनका ही था। इसका महायुति को बहुत फायदा हुआ है। शिंदे गुट के नेता बिहार पैटर्न की याद दिलाने से भी नहीं चूक रहे हैं।

देशभर में बदल रहा मौसम का मिजाज

पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी ठंड, दक्षिण राज्यों में बारिश की आशंका

नई दिल्ली (ईएमएस)। देशभर में ठंड बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल रहा है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली-एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो-तीन दिन में तापमान में और गिरावट आ सकती है। उत्तर भारत के राज्यों में जहां ठंड बढ़ रही है, तो वहीं दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु और केरल समेत कुछ स्थानों में भारी बारिश की आशंका है। दिल्ली-एनसीआर में पारा गिरना शुरू हो जाएगा। पिछले दो-तीन दिनों से दिल्ली में तापमान सामान्य बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री है। आगे दो-तीन दिन में मौसम ऐसा ही रहने वाला है, उसके बाद इसमें गिरावट आएगी। आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मौसम बिल्कुल सामान्य है। आने वाले दो-चार दिन में घने कोहरे की संभावना नहीं है। सामान्य रूप से जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, तापमान में गिरावट आएगी।

पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू-कश्मीर बर्फबारी

पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर में हल्के और मध्यम स्तर बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल में भी थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है। इसके अलावा बाकी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा असर नहीं पड़ा है। मौसम बदल रहा है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आएगी। इसके तीन-चार दिन बाद हम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मध्यम से घने कोहरे की अपेक्षा कर सकते हैं। सोमवार को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के तट की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण 25 से 28 नवंबर तक तमिलनाडु और केरल समेत दक्षिण भारत में भारी बारिश की आशंका है।

तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए का सीएसआर फंड लौटाया

हैदराबाद (ईएमएस)। युवाओं में कौशल क्षमताएं विकसित करने के उद्देश्य से अडानी ग्रुप से लिया गया 100 करोड़ रुपए का सीएसआर फंड तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने वापस लौटा दिए हैं। कांग्रेस सरकार ने यह निर्णय अमेरिका में अडानी समूह पर लगे घूस के आरोपों के बाद लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अडानी समूह से किसी भी तरह की धनराशि स्वीकार करने से इंकार किया है। इससे पहले अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी और सात अन्य पर सौर ऊर्जा से जुड़े अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। वहीं अडानी समूह ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इससे इनकार किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार ने अडानी समूह सहित किसी भी संगठन से यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए कोई पैसा नहीं लिया है। रेड्डी ने कहा, तेलंगाना सरकार ने अडानी समूह से यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए कोई धनराशि या दान नहीं लिया है। सरकार ने अडानी समूह को लिखा कि वे कौशल विश्वविद्यालय के लिए दिए गए 100 करोड़ रुपये स्वीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को टेंडर्स आमंत्रित करने चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से सही प्रक्रिया के साथ टेंडर्स आवंटित किए जाएं, चाहे वह अडानी हो, अंबानी हो या टाटा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई कंपनियों ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को पैसा दिया है। इसी तरह अडानी ग्रुप ने भी हमें 100 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है।

100 करोड़ रुपए लेने पर हुई थी आलोचना

बता दें कि 18 अक्टूबर को गौतम अडानी ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को 100 करोड़ रुपये का चेक सौंपा था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। इस खबर के सामने आने के बाद राज्य की विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस की आलोचना की थी। भाजपा और भारत राष्ट्र समिति ने कांग्रेस पर अडानी मामले में ढोंग करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी के पूरे दिन अडानी अडानी चिल्लाने के बावजूद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आगे बढ़ कर गौतम अडानी से दान स्वीकार करते हैं।

इस्कॉन बांग्लादेश के चिन्मय प्रभु हिरासत में

उन पर देशद्रोह का केस

ढ़ाका (ईएमएस)। बांग्लादेश इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णा दास प्रभु को सोमवार दोपहर देशद्रोह के केस में हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप है। चिन्मय प्रभु के सहायक आदि प्रभु ने बताया कि उन्हें ढाका के मिंटू रोड स्थित डीबी कार्यालय ले जाया गया।

बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक, चिन्मय प्रभु ढाका से चटगांव जाने के लिए हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे, यहीं से उन्हें डिटेक्टिव पुलिस ने हिरासत में लिया। चिन्मय प्रभू को चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों के विरोध में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था।

आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराने का आरोप

25 अक्टूबर को चटगांव के लालदीघी मैदान में नातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी, इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। इसे लेकर चिन्मय कृष्ण दास पर राष्ट्रीय झंडे की अवमानना और अपमान करने का आरोप लगाया गया है।

इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ था

बांग्लादेश में सत्ता संग्राम के दौरान 6 अगस्त को बांग्लादेश के खुलना जिले में एक इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया था। इसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को जला दिया गया था। इस हमले के बाद चिन्मय दास ने कहा था कि चटगांव में भी तीन अन्य मंदिरों पर भी खतरा है। हिन्दू समुदाय मिलकर उनकी सुरक्षा में लगा है। दास का कहना था कि हिंसा से बचने के लिए हिन्दू त्रिपुरा और बंगाल के रास्ते भारत में शरण ले रहे हैं। चिन्मय दास हिन्दू मंदिरों की सुरक्षा के मुद्दे को काफी समय से उठाते रहे हैं।

अब पैन कार्ड पर होगा क्यू-आर कोड, केंद्र सरकार ने पैन 2.0 जारी करने का निर्णय लिया

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने पैन 2.0 जारी करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसमें स्थायी खाता संख्या यानी पैन को पूरी तरह से उन्नत बनाने और इसके आंकड़ों की सुरक्षा तथा पैन से संबंधित शिकायतों के स्थायी समाधान का प्रावधान है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है और इस पर 1435 करोड़ रूपये का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में मौजूदा पैन को पूरी तरह बदल कर उन्नत बनाया जायेगा और यह क्यू आर कोड आधारित तथा पूरी तरह ऑनलाइन होगा। इसके लिए व्यक्ति को किसी तरह की राशि खर्च नहीं करनी होगी और पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति का पैन नम्बर नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि नये पैन में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को भी चाक चौबंद बनाया जायेगा। पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है और इससे बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और त्वरित सेवा वितरण, डेटा स्थिरता का एकल स्त्रोत सुनिश्चित होगा। पैन 2.0 परियोजना निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन के उपयोग को सक्षम करके डिजिटल इंडिया में निहित सरकार की दृष्टि के अनुरूप है।

अमेरिका के बाद अब बांग्लादेश ने बढ़ाई अडाणी समूह की मुश्किलें

अडाणी के साथ बिजली डील की जांच करेगी एजेंसी

ढाका(ईएमएस)। अमेरिका में रिश्वत देने के आरोप में घिरे अडाणी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते अडाणी ग्रुप के साथ हुए पावर एग्रीमेंट की जांच के लिए एक एजेंसी गठित करने की सिफारिश की गई है। अंतरिम सरकार की तरफ से गठित समिति ने इस एजेंसी के गठन की सिफारिश की है। साथ ही शेख हसीना के पीएम रहते हुए छह अन्य बड़े एनर्जी और पावर एग्रीमेंट के जांच की भी मांग की गई है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पावर, एनर्जी और खनिज संसाधन मंत्रालय की समीक्षा समिति ने 2009 से 2024 तक पावर प्रोडक्शन एग्रीमेंट को लेकर किए गए समझौते की जांच के लिए एजेंसी नियुक्त करने की सिफारिश की है। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि समीक्षा समिति सात प्रमुख एनर्जी और पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रही है। इसमें अडाणी (गोड्डा) बीआईएफपीसीएल 1234.4 मेगावाट कोल फायर्ड प्लांट भी शामिल है। छह अन्य समझौतों में से एक चीनी कंपनी के साथ हुआ है, जिसने 1320 मेगावाट का कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाया है। बयान में यह भी कहा गया है कि समिति ने कई सबूत जुटाए हैं, जिनके आधार पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रक्रियाओं के मुताबिक समझौतों को रद्द या पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य कॉन्ट्रेक्ट की जांच के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगा गया है।

2016 में हसीना सरकार के साथ करार किया था

अडाणी ग्रुप का गोड्डा पावर प्लांट ग्रुप का पहला इंटरनेशनल पावर प्लांट है। इसमें झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया था। इससे ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को बिजली की सप्लाई की जा रही है। 2016 में इसे लेकर शेख हसीना सरकार के साथ करार किया गया था। अडाणी पावर लिमिटेड ने 10 अप्रैल 2023 से अपने पावर प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट शुरू किया था। कंपनी ने 2017 में पावर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत 25 सालों तक गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने के लिए डील की थी। अडाणी ग्रुप ने पिछले महीने बांग्लादेश सरकार को 800 मिलियन डॉलर के बकाया बिजली आपूर्ति बिल के बारे में एक लेटर भेजा था। इसे लेकर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का कहना था कि उन्होंने डॉलर संकट के बावजूद पहले ही 150 मिलियन डॉलर का भुगतान कर दिया है।

धोखाधड़ी के ?शिकार व्य?क्ति के खाते से गायब हुए 2.6 लाख वापस करे बैंक: हाईकोर्ट

- हर्जाने के रूप में याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये का भुगतान भी करे

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया है कि वह साइबर धोखाधड़ी के शिकार 55 वर्षीय व्यक्ति के खाते से गायब हुए 2.6 लाख रुपये वापस करे। यह मामला 2021 में सामने आया था, जब याचिकाकर्ता एक फिशिंग और विशिंग हमले का शिकार हुआ। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि बैंक उक्त राशि पर 9 फीसदी वार्षिक ब्याज और हर्जाने के रूप में याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये का भुगतान करे। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने अपने फैसले में भारतीय स्टेट बैंक को स्पष्ट सेवा कमी का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी की सूचना मिलने के बावजूद बैंक की प्रतिक्रिया ढीली, दोषपूर्ण और समय पर नहीं थी। अदालत ने कहा कि बैंक को ग्राहक के साथ एजेंट की तरह व्यवहार करते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और धोखाधड़ी का पता लगते ही तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने अपराधियों के साथ कोई ओटीपी साझा नहीं किया था, फिर भी उसके खाते से राशि निकाल ली गई। न्यायमूर्ति ने कहा कि बैंक ने संदिग्ध खातों को चार्जबैक, पुनर्प्राप्ति या फ्रीज करने जैसे कदम उठाने में लापरवाही बरती। अदालत ने विशेष रूप से एसबीआई की आलोचना करते हुए कहा कि उसने आईडीएफसी बैंक और वन97 कम्युनिकेशन में रखे गए खातों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने कहा कि ग्राहक सेवा किसी भी बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर धोखाधड़ी के मामलों में। इस मामले में बैंक का रवैया गंभीर रूप से असंतोषजनक और गंभीर सेवा कमी का उदाहरण था। अदालत के इस आदेश से साइबर धोखाधड़ी

जन हितैषी

सदनद्वय की कार्रवाई का संभल-हिंसा की भेंट चढ़ जाने से आशय

संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यह सत्र हंगामेदार रहने वाला है, सो पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई हंगामे के चलते 27 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बस अंतर यह रहा कि हंगामे की वजह बदल गई है। पहले समझा जा रहा था कि गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा जैसे मामलों को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है, लेकिन अचानक से संभल हिंसा सामने आ गई, जिस पर विपक्ष ने चर्चा की मांग रखी। इसी बीच हंगामा हुआ जिसके चलते पहले लोकसभा की कार्रवाई एक घंटे के लिए और बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई अगले कार्यदिवस बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मतलब यह कि संभल में जो हिंसा हुई और 4 से 5 लोगों को अपनी जांन से हाथ धोना पड़ गया। यह वाकई गंभीर चिंतनीय विषय है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं तो हैरानी की बात भी नहीं है। वायनाड लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी का इस मामले में जो बयान आया उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के संभल में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वाकई इस संवेदनशील मामले में बिना दूसरे पक्ष को सुने और बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासनिक स्तर पर जो हड़बड़ी में कार्रवाई की गई, वह दिखाता है कि राज्य सरकार ने खुद ही माहौल को खराब किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की बात कहते हुए प्रियंका ने सत्ताधारियों पर भेदभाव, अत्याचार और फूट डालने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इससे पहले संभल मामले में ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने दावा किया था कि संभल में एक गंभीर घटना हुई है। इसके मुताबिक चुनाव पर चर्चा रोकने की गरज से सुबह-सुबह जानबूझकर एक सर्वेक्षण टीम को भेज दिया गया, जिसका उद्देश्य अराजकता पैदा करना था। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब मस्जिद का सर्वेक्षण पहले ही हो चुका था, तो फिर से नया सर्वेक्षण क्यों किया गया और वह भी सुबह-सुबह और बिना किसी तैयारी के? वैसे यह कहना गलत भी नहीं होगा कि देश में मौजूद ज्वलंत समस्याओं और अडानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों से देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए कथित तौर पर सरकारों द्वारा संभल हिंसा जैसे प्रयोग किए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। सूबे की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिंह लगाने जैसी घटना यूं ही अचानक तो नहीं हो सकती है। इसके पीछे राजनीतिक घडयंत्र की बू आती है। जिसे विपक्ष लगातार उजागर करने की कोशिश में लगा हुआ है। खासतौर पर तब जबकि संसद के शीतकालीन सत्र के आगाज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हुए नजर आते हैं कि यही आशा करता हूं कि शीतकालीन सत्र का माहौल भी शीत रहे। अब समझने वाली बात तो यह है कि प्रकृति की तरह माहौल को शीत रखने के लिए कुछ बेहतर कार्य भी तो करने ही पड़ते हैं। वही पीएम मोदी विपक्ष पर भी वार करने से नहीं चूकते हैं और यह भी कह जाते हैं कि यह दुर्भाग्य ही है कि मुट्ठीभर लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को हुडदंगबाजी से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को जनता देखती और सजा देती है। जिन्हें जनता ने 80 बार नकारा वो संसद का काम रोकते हैं। यह कहते हुए शायद पीएम मोदी भूल जाते हैं कि किस जतन और सालों की मेहनत के बाद भाजपा अब गठबंधन के सहारे केंद्र में बागडोर संभालने पहुंची है। आईने के मिजाज की तरह वो बात करते नजर आते हैं, ऐसे ही आईने के लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है- आईने की फितरत भी किस तरह सियासी है, ये भी शक्त इंसां को जाहिरी दिखाता है। जहां तक संभल हिंसा का सवाल है तो बताया जा रहा है कि हिंसा उस वक्त भड़क उठी जब मुगलकालीन एक मस्जिद का अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण करने दोबारा टीम पहुंची थी। भीड़ के बीच में से ही कुछ लोगों ने सर्वे टीम पर पत्थरबाजी शुरु कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे गए और फायरिंग भी हुई। इस हिंसा में इंसानी खून बहा और मौतें भी हुईं। इसके बाद पुलिस ने मामले भी दर्ज किए और लोगों की गिरफ्तारियां भी हुईं। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जहां राज्य की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है तो वहीं संसद में विपक्ष ने मोदीनीत सरकार को भी घेरने में कोई कोर-कसर वाकी नहीं रखी है। सदन में संभल हिंसा पर चर्चा की मांग करता विपक्ष और हंगामे की भेंट दोनों सदनों की कार्रवाई भेंट चढ़ गई। अंततः धर्म और आस्था के नाम पर जिस तरह से देश में हिंसक घटनाओं को प्रायोजित करने का खेल चलता रहा है, वह किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह के मामलों को हल करने के लिए भारतीय संविधान की गाइडलाइन के तहत न्यायपालिका का सहारा लिया जाना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि शांतिप्रिय ढंग से मसले का हल निकल आए। पर अफसोस कि जहां राजनीति समाहित हो जाती है, वहां समस्या का समाधान नहीं निकलता, बल्कि वही होता है जो उत्तर प्रदेश के संभल में देखने को मिल रहा है।

संविधानः हम भारत के लोग'

भारत रत्न, भारतीय बहुज़, डां भीम राव रामजी अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता थे। उन्हें 1947 में संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं 1946 में देश के पूर्व राष्ट्रपति डां राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अतुलनीय, भारतीय संविधान यानी विश्व के महान लोकतंत्र का धर्मग्रंथ और आत्मा है। जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बयर 1949 को ग्रहण किया गया। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। साथ ही इसमें पांच परिशिष्ठ भी जोड़ दिए गए हैं, जो कि प्रारंभ में नहीं थे। संविधान सभा के सभी 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इसके पश्चात 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसे पारित करने में अभूतपूर्व 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

अभिभूत, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। संविधान भाग 3 व 4 नीति निर्देशक तत्त्व मिलकर संविधान हृदय, चेतना और रीढ कहलाते है। क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति-निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यथार्थ प्रदत्त अधिकार हमारे राष्ट्र के परम वैभव और जनकल्याण के लिए सारगर्भित हैं।

विशेष, संविधान विधान भर नहीं है। यह भारतीय संस्कृति है। संविधान की देह भारतीय है। इसलिए कि भारतीय, सभ्यता, संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है। हमारी जो उदात्त जीवन परम्पराएं हैं। संविधान उसे एक तरह से व्याख्यायित करता है। संविधान की नियमावली पर गूढ़ नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे संविधान का आधार भगवान श्रीराम के आदर्शों का भी पालन करता है। उनके आदर्श समाज के प्रारूप को ही नहीं अपितु देश के संविधान को तय करने और देश का बेहतर संचालन करने में भी प्रासंगिक हैं। ऐसा ही कुछ विचार आया होगा भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि पर चित्र बनाने वाले महान चित्रकार नंदलाल बोस के दिमाग में। 'सर्वधर्म समभाव' की विचारमाला को अपने मानकों में पिरोने वाले भारतीय संविधान की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ऐसे चित्र बनाए। जो भारत की गौरवगाथा के अहम अध्याय हैं। जिनका हमारी अलौकिक जीवन शैली में विशेष योगदान रहा है।

स्तुत्य, भारतीय संविधान हम भारत के लोगों के लिए हमारी अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत जनित स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श मूल्यों के प्रति एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। संविधान की मूल प्रति पर नटराज भी हैं और श्रीकृष्ण भी। वहां शांति का उपदेश देते भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोबिंद सिंह भी हैं। हिंदू धर्म के एक और अहम प्रतीक शतदल कमल भी संविधान की मूल प्रति पर मौजूद है। स्वतंत्रता वीर शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस का ओज है। महाराजा विक्रमादित्य का दरबार, नालंदा विश्वविद्यालय की मुहर और पृथ्वी पर गंगावतरण आलोकित है। हालांकि ये तस्वीरें संविधान का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी ये संविधान की मूल प्रति के अभिन्न अंग हैं। जो मूलतः भारतीय संविधान के भारतीय चैतन्य को ही परिभाषित करते हैं। भारतीय ज्ञान परम्परा के आलोक में निर्मित भारतीय संविधान भारत की ऋषि परम्परा का धर्मशास्त्र है। भारतीय जीवन दर्शन का ग्रंथ है। वस्तुतः भारत का संविधान देश को संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है और अपने नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्रत्याभूति देता है। अनुकरणीय, हमें असीम गर्व और गौरव सार्थक अनुभूति होती है। सत्यमेव जयते! (लेखक- हेमेन्द्र क्षीरसागर / ईएमएस) (हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार, बालाघाट, मप्र)

संभल से इम्फाल तक हिंसा की एक ही बीमारी

उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा की आग में जल रहा है । हिंसा में 4 लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर में हिंसा का जघन्य रूप सामने है लेकिन सरकार महाराष्ट्र में जीत का जश्न मना रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकारी पार्टी के लोग मस्जिदों के नीचे दबे मंदिरों को खोजने की सनक में गड़े मुर्दे उखाड़ने से पीछे नहीं हट रहे। वैसे भी उसका नारा है बटोगे तो कटोगे का है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ने समाज को एक नहीं किया बल्कि बाँट दिया है। ये बँटवारा मणिपुर में पूरी तरह हो चुका है और उत्तर प्रदेश में जारी है। उत्तर प्रदेश बहराइच से होता हुआ साम्भल तक आ पहुंचा है।

मणिपुर और संभल की बीमारी एक जैसी है ,लेकिन उसका इलाज अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकार संरक्षित लोग / संस्थाएं जामा मस्जिद की जामा तलाशी लेने के लिए अदालती आदेशों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महकमे का सहारा ले रही है। ये काम अयोध्या की बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ था और आज तक जारी है। कभी ज्ञानवापी के रूप में तो कभी संभल के रूप में। ये घृणित कोशिश उत्तराखंड में भी हुई और देश के दूसरे हिस्सों में भी। देश में लोगों के पास महंगाई के खिलाफ लड़ने का माद्दा नहीं है । लोग बेरोजगारी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, महिला हिंसा के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते । भूख-गरीबी के खिलाफ एकजुट होकर अदालतों के चक्कर नहीं काट सकते, लेकिन जामा मस्जिद की जामा तलाशी के लिए अदालतों के चक्कर काटने की फुरसत उन्हें है।

देश में स्पष्ट क़ानून है कि आजादी के बाद जिन पूजा स्थलों की जो स्थिति है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी ,किन्तु देश की अदालतों को इस कानून से शायद कोई लेना-देना नहीं है। वे कभी भी ,किसी को भी किसी भी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दे सकतीं हैं। अदालतों को भी सियासत और सत्ता की तरह गड़े मुर्दे उखाड़ने में मजा आता है शायद। अन्यथा क्या जरूरत है किसी मस्जिद की जड़ें खोदने की ? माना कि अतीत में किसी मस्जिद को, किसी मंदिर को जमीदोज कर बनाया गया होगा, लेकिन क्या आज फिर वो ही गलती जानबूझकर दोहराये जाने की जरूरत है ?।

महाराष्ट्र विधान सभाचुनावों में मिली प्रचंड जीत ने भाजपा और उसके अनुसांगिक संगठनों का हौसला और बढ़ा दिया है। वे हर कीमत पर अल्पसंख्यक समाज को सबक सिखाना चाहते हैं और इसी का नतीजा बहराइच और संभल की हिंसा है। सरकार और सरकारी लोगों को रोज-रोज ये नाटक करने के बजाय एक बार में देश की तमाम मस्जिदों के सर्वेक्षण का आदेश अदालत से हासिल कर लेना चाहिए। आपको शायद पता न हो इसलिए मै बता दूँ कि देश में एक -दो नहीं कोई 6 लाख छोटी-बड़ी मस्जिदें है। इनमें से अधिकांश के नाम जामा मस्जिद हैं। क्या सरकार इन सबका सर्वे करा सकती ही ? मेरे ख्याल से सरकार को वक्फ बोर्ड क़ानून में संशोधन करने के इन लाखों मस्जिदों का सर्वेक्षण करने के लिए एक विधेयक लाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में जो काम 5 -6 दिसंबर 1992 को अयोध्या से शुरू हुआ था वो काम आज भी जारी है। कभी ज्ञानवापी के रूप में कभी संभल के रूप में तो कभी उत्तराखंड की किसी मस्जिद को तोड़ने के रूप में। सरकार देश को धर्मनिरपेक्ष नहीं देखना चाहती । सरकार का एजेंडा देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने का है ,इसलिए बेहतर हो कि केंद्र सरकार एक क़ानून लेकर पहले देश को मस्जिद विहीन करे ,बाद में देश को हिन्दू राष्ट्र बनाये। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को भी हिंदुस्तान से बेदखल कर दुनिया के तमाम मुस्लिम राष्ट्रों में तकसीम कर देना चाहिए। सरकार ये कर सकती है। सरकार के तमाम मुस्लिम देशों से मैत्रीपूर्ण रिश्ते भी हैं। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं पायेगी।

इस समय देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है । डेढ़ साल से मणिपुर यदि जल रहा है तो केवल केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी की वजह से। मणिपुर में धार्मिक स्थलों को जिस तरह से तबाह किया गया है उसकी कोई मिसाल हमारे इतिहास में नहीं मिलती। क्या भविष्य में मणिपुर की तरह उत्तर प्रदेश या दूसरे सूबों में दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को आग के हवाले किया जाएगा ? क्या उनकी नीवों को सर्वे के नाम पर खोदा जाएगा ? क्या जानबूझकर वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की कोशिश की जाएगी ? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके उत्तर इस देश के अल्पसंख्यक ही बल्कि बहुसंख्यक समाज को भी चाहिए।

संसद का शीत सत्र शुरू हो चुका है। देखना ये है कि संसद में देश की भलाई के लिए कोई काम होता है या फिर संसद हिन्दू-मुसलमान करती रह जाएगी। ये देश इस मामले में बदनसीब है कि इसे आजादी के पहले भी साम्प्रदायिक हिंसा की आएग में जलना पड़ा और आजादी के 77 साल बाद भी यहां बहराइच और संभल काण्ड हो रहे हैं। सांप्रादियक हिंसा से ग्रस्त इलाकों में शान्ति स्थापना केलिए हमारे पास सशस्त्र बल हैं,बंदूकें हैं, आंसू गैस के गोले हैं,लाठियां हैं लेकिन कोई गांधी नहीं है जो वहां जाकर उपवास कर सके । लोगों से शांति की अपील कर सके। हमारे पास आज गांधी जी नहीं ,मोदी जी हैं और मोदी जी संभल जाने से रहे ,उन्हें उपवास करना आता ही कहाँ है / वे तो हिमालय की कंदराओं में ध्यान लगा सकते हैं । उन्हें तो डेढ़ साल से धधक रहे मणिपुर जाने की फुरसत नहीं है। हे भगवान इस देश की रक्षा कीजिये। (लेखक - राकेश अचल / ईएमएस)

चुनाव परिणाम : सत्ता पक्ष को फिर मिला जनादेश

देश के दो राज्यों के साथ कुछ राज्यों के उपचुनाव के परिणाम ने सत्ता पक्ष के प्रति अपना जनादेश दिया है। हर चुनाव में सत्ता के प्रति जनता में किसी न किसी बात पर आक्रोश रहता है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखण्ड के चुनाव में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जनता ने फिर से उन्हीं सरकारों को फिर से सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दी है, जो सत्ता में थी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र और झारखण्ड में सत्ता धारी गठबंधन को पहले से ज्यादा सीटें मिली हैं। यह जनादेश न तो किसी के उछलने का मार्ग तैयार करता है और न ही किसी को नकारने की स्थिति पैदा करता है। जहां तक खुशियाँ मनाने की बात है तो महाराष्ट्र में भाजपा नीत गठबंधन जीत की खुशी मना रहा है तो झारखण्ड में इंडी गठबंधन के गले में विजयी माला पहनाई गई है। वहीं उपचुनाव में सबको ख़ुशी और सबक दोनों ही दिए हैं।

महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अपने हिसाब से राजनीतिक विश्लेषण किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के लिए इन चुनावों में प्रादेशिक रूप से जय और पराजय दोनों ही सन्देश प्रवाहित हो रहे हैं। किसी के लिए ख़ुशी तो किसी के लिए गम की स्थिति पैदा करने वाले परिणाम ने यह तो साबित कर दिया है कि देश में किसी एक राजनीतिक दल का न तो व्यापक प्रभाव है और न ही कम सीट प्राप्त करने वाले को कमतर आँका जा सकता है। इस चुनाव की सबसे ख़ास बात यह मानी जा सकती है कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सकी, जिससे यह सन्देश निकल रहा है कि अब भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा गठबंधन के सहारे ही तय होगी। वर्तमान में राजनीति दो विचार धाराओं के बीच है, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बनाकर चलने वाले राजनीतिक दलों का विचार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विचारों से तालमेल रखने वाले दलों की बानगी है। इतना ही नहीं इन चुनावों एक दूसरे के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया, वह राजनीतिक हिसाब से भले ही जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन आम नागरिकों के समक्ष भ्रम जैसी स्थिति को ही प्रादुर्भित करती हैं।

महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम भाजपा के लिए निश्चित ही अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन झारखण्ड में सरकार बनाने का सपना लेकर मैदान में उतरी भाजपा को फिर से तैयारी करनी होगी। झारखण्ड के परिणाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति उपजी सहानुभूति को आधार बताया जा रहा है। पिछले दिनों झारखण्ड में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से अलग होना पड़ा था। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने चुनाव में इसी को अपना राजनीतिक हथियार बनाया था और चुनाव में अपने पक्ष में वातावरण बनाया। ऐसा लगता है कि झारखंड में भाजपा अपनी ताकत और कमजोरी को भाँपने में विफल हो गई। झारखण्ड में भाजपा इतनी अप्रभावी नहीं कही जा सकती, जैसा उसका इस चुनाव में प्रदर्शन रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा के प्रादेशिक नेताओं की तनातनी जगजाहिर थी, जिसका परिणाम भाजपा के लिए ठीक नहीं था। हालाँकि इस चुनाव में भाजपा ने पिछली गलती को सुधारने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह सत्ता के सीढ़ी का निर्माण कर पाने में असफल रही। अब झारखण्ड में फिर से झारखण्ड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री होंगे, यह भी तय लगता है।

परिणाम के बाद अब महाराष्ट्र के चुनावों के बारे में जो राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, उसके अनुसार यही कहा जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में राजनीतिक हवा अलग अलग दिशा में बह रही थी। जिसने हवा का रुख भांप लिया, वह हवा के साथ ही चला और सत्ता प्राप्त करने में सफलता हासिल की। महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस के साथ रहने वाले शिव सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार कर शायद यही सन्देश दिया है कि यह सत्ता के लिए किया गया बेमेल गठबंधन ही था। महाराष्ट्र में ऐसे जनादेश का क्या अर्थ होना चाहिए कि एक गठबंधन जीत गया तो दूसरा गठबंधन हार गया। इसी प्रकार झारखण्ड में भी जनादेश की भी समीक्षा की जाने लगी है।

पिछले पांच साल में महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीतिक उठापटक हुई थी, उसके केंद्र में कौन था, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडी गठबंधन की मानें तो उसने इसका सारा ठीकरा भाजपा के मत्थे मढ़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इस राजनीतिक धमा चौकड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिव सेना ने अपने विभाजन के रूप में चुकाई। जो धड़े अलग हुए वे भाजपा के साथ जाकर खड़े हो गए और महाराष्ट्र में सरकार बनाई। कहा जा रहा है कि जनादेश ने भाजपा के साथ वाली शिव सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को असली होने का प्रणाम पत्र दे दिया है। अब महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन की ही सरकार बनेगी, यह तय है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके कयास भी लगने लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भाजपा ने शानदार वापसी की है। ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि एकनाथ शिंदे ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके पीछे राजनीतिक कारण यह भी माना जा रहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सहयोगी दलों की जरुरत है, इसलिए भाजपा अपने सहयोगी दलों को अब नाराज नहीं कर सकती। दूसरी बात यह भी है भाजपा ने एकनाथ शिंदे को जिस प्रकार से चौकाने वाले अंदाज में मुख्यमंत्री बनाया था, वह हर किसी के लिए आश्चर्य ही था। अब यह भी हो सकता है कि भाजपा ने जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया, वही प्रयोग शिंदे के साथ भी किया जा सकता है। (लेखक – सुरेश हिंदुस्तानी/ ईएमएस) (सुरेश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार)

शर्मनाक है विध्वंस को महिमामंडित करना

साहित्य, मानवीय अभिव्यक्ति का एक ऐसा रूप है जो संस्कृति का प्रसार करता है। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। साहित्यकार अपनी रचनाओं में समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। साहित्य, जीवन के प्रचलन के अनुसार गतिशील रहता है। गैर-काल्पनिक गद्य, काल्पनिक गद्य, कविता, नाटक, और लोक कथाएं आदि साहित्य के प्रमुख रूप हैं। साहित्यिक भाषा, किसी भाषा का वह रूप है जिसका उपयोग औपचारिक, अकादमिक, या विशेष रूप से विनम्र लहजे में लिखते समय किया जाता है। साहित्य समाज के मर्म का भी दर्पण है। यह साहित्य ही है जिसके द्वारा शब्दों के माध्यम से बड़े ही प्रभावी तरीक़े से अपनी बात कही और दूसरों तक पहुंचाई जाती है। हमारे देश में हिंदी व उर्दू साहित्य का एक सबसे प्रभावी नाम था मुंशी प्रेमचंद। उनके उपन्यासों व कहानियों में प्रायः ग़रीबी,सामाजिक अन्याय, सामाजिक व साम्प्रदायिक सद्भाव सहित तमाम मानवीय पहलुओं का ज़िक्र हुआ करता था। इसी तरह प्रेमचंद के समकक्ष अंग्रेजी साहित्य में भी ऐसे अनेक साहित्यकार हुये हैं जिन्होंने सामाजिक मुद्दों और यथार्थवाद को इसी तरह संबोधित किया। इनमें चार्ल्स डिकेंस को जहां गरीबों के संघर्षों के चित्रण और सामाजिक अन्याय की आलोचना के लिए जाना जाता है वहीं विशेष रूप से ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपर फ़ील्ड जैसी रचनाओं के लिये भी वे प्रसिद्ध हैं। इसी तरह मार्क ट्वेन के आख्यानों में अक्सर जाति और वर्ग के विषयों पर प्रकाश डाला जाता था, जैसा कि द एडवेंचर्स ऑफ़ हकलबेरी फिन में देखा गया है। वहीं टोनी मॉरिसन जोकि बेलव्ड जैसे उपन्यासों में अीक़ी अमेरिकी अनुभवों और सामाजिक मुद्दों की उनकी खोज प्रेमचंद के हाशिए पर पड़े समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रतिध्वनित होती है। प्रेमचंद की ही तरह इन लेखकों ने भी अपने आख्यानों का उपयोग सामाजिक मानदंडों और अन्याय की आलोचना करने के लिए किया।

लियो टॉल्स्टॉय ने भी प्रेमचंद के लेखन को प्रभावित किया। उन्होंने टॉल्स्टॉय की नैतिक कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया, जिससे उन्हें हिंदी टॉल्स्टॉय की उपाधि मिली। इसी तरह गुस्ताव फ़्लोबर्ट की कथात्मक शैली भी प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थवाद पर ध्यान केंद्रित करने के समान है। मैक्सिम गोर्की ने भी विशेष रूप से निम्न वर्गों के संघर्षों के संबंध में प्रेमचंद के साथ विषयगत चिंताओं को साझा किया। इसी तरह शेक्सपियर हों या रविंद्र नाथ टैगोर,इन जैसे अनेक लेखकों व साहित्यकारों ने अपने लेखन में मानवीय संवेदनाओं का बख़ूबी ज़िक्र किया है। वैसे भी हमारा देश गांधी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले देश के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। इसलिये ह ा ह ा हिंसा,विध्वंस,नफ़रत,विद्वेष,साम्प्रदायिकता तबाही बर्बादी जैसे अमानवीय पहलुओं की कोई गुंजाईश नहीं होनी चाहिये।

परन्तु ब्रिटिश कंपनी जे सी बैमफ़ोर्ड एक्सकेवेटर लिमिटेड (जेसीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेसीबी (इंडिया) जो ब्रिटिश कंज़र्वेटिव पार्टी के सबसे प्रभावशाली दान दाताओं में से एक रही है, इसी जेसीबी कंपनी ने लेखकों के लिए एक साहित्य पुरस्कार की स्थापना की है। ग़ौर तलब है कि यही जे सी बी कंपनी है जो इज़राइली रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध के तहत फ़िलिस्तीन में मकानों को ध्वस्त करने और अवैध इस्राईली बस्तियों के विस्तार के लिए जेसीबी बुलडोज़र मुहैय्या करा रही है। इसी जे सी बी के बुलडोज़र ग़ज़ा में तबाही मचाये हुये हैं। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के दख़ल के बाद भले ही जे सी बी के बुलडोज़रों द्वारा ढहाए जाने वाले भवनों की संख्या में अब विराम लग गया हो। परन्तु गत एक दशक से देश के ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी शासित अनेक राज्यों में सत्ता शक्ति का दुरूपयोग करते हुये धर्म व जाति-विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया और शासन द्वारा अदालत की शक्तियों को अपनी हाथों में लेने की कोशिश की गयी, जिसने पूरे विश्व में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया।

और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि इसी विध्वंसकारी मशीन का भारत से लेकर अमेरिका तक इन्हीं दक्षिणपंथियों द्वारा महिमामंडन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मशीन का विदेशों में प्रदर्शन किया गया। और हद तो तब हो गयी जब गाँधी के राज्य गुजरात में अप्रैल 2022 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटिश जे सी बी कम्पनी का दौरा करते हैं और साथ ही बुलडोज़र पर खड़े होकर फ़ोटो कराते हैं। साथ ही अपने इसी दौरे में वे गाँधी जी के आश्रम में जाकर उनका चरख़ा भी चलाते हैं। सवाल यह है कि जो जे सी बी कंपनी भारतीय लेखकों की विविधता का जश्न मनाते हुए साहित्यिक पुरस्कार देने के घोषणा कर रही हो उसी कंपनी द्वारा ऐसी विध्वंसकारी मशीन का निर्माण व जनसंहारक उपयोग किया जाना जिससे कि वह दंड के रूप में लाखों लोगों के जीवन,उनके घरों व आजीविका को नष्ट करने में भागीदार हो, ऐसे दोहरेपन में आख़िर साहित्यिक पुरस्कार की क्या गुंजाईश ?

यही वजह है कि भारतीय लेखकों सहित विश्व के सौ से अधिक उपन्यासकारों,लेखकों,कवियों,अनुवादकों और प्रकाशकों ने ब्रिटिश बुल्डोजर निर्माता और एक साहित्यिक पुरस्कार की आयोजक कंपनी जेसीबी की आलोचना करते हुए एक खुला पत्र लिखकर साफ़ शब्दों में यह कहा है कि 'जेसीबी साहित्य पुरस्कार' कोई पुरस्कार नहीं बल्कि यह इस कंपनी का एक पाखंड है क्योंकि जेसीबी साहित्य पुरस्कार' की घोषणा करने वाली यही कंपनी भारत और फ़िलस्तीन में ग़रीबों तथा हाशिये पर पड़े ग़रीब लोगों की ज़िंदिगी 'उजाड़' रही है और जो 'दंड के रूप में इतने सारे लोगों के जीवन और आजीविका को नष्ट करने में भागीदार है। 'लेखकों ने पत्र में यह भी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विभिन्न राज्यों में मुसलमानों के घरों, दुकानों और उपासना स्थलों को ध्वस्त करने के लिए 'व्यवस्थित अभियान' में लगातार जेसीबी बुलडोज़र का इस्तेमाल किया है और इस परियोजना को 'बुलडोज़र न्याय' का नाम दिया गया है, जो बेहद परेशान करने वाला है। लेखकों ने अपने खुले पत्र में यह भी कहा है कि ''हम साहित्यिक समुदाय के समर्थन के ऐसे कपटपूर्ण दावों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह पुरस्कार जेसीबी के हाथों पर लगे ख़ून को नहीं धो सकता। भारत के उभरते लेखक इससे बेहतर पुरस्कार के हक़दार हैं। कंपनी और पुरस्कार देने वालों की ओर से इस तरह का पाखंड निंदनीय है। इसे भारतीय साहित्य के लिए एक बहुत ही 'प्रतिष्ठित' साहित्यिक पुरस्कार के साथ जोड़कर हरगिज़ नहीं देखा जा सकता। न ही इस पुरस्कार का स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विविधता और बहुलवाद को बढ़ावा देने से कोई लेना-देना है। मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करने वाले लेखकों के लिये यह महत्वपूर्ण व ज़रूरी है कि वे मानवाधिकारों के इस घोर उल्लंघन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं।''क्योंकि विध्वंस को महिमामंडित करना शर्मनाक है। (लेखक – तनवीर जाफ़री/ईएमएस)

शब्द पहेली - 8199

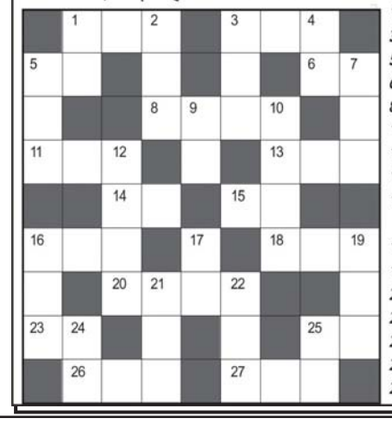

बाएँ से दाएँ

1. कथा,गाथा-3
3. भगौना-3
5. पुष्पहार-2
6. वायदा,कसम-2
8. अभिष्ट इच्छापूर्ति,वर-4
11. योग्य,उपयुक्त-3
13. चिंतन,सोच-विचार-3
14. ताश का एक खेल-2
15. संजय दत्त की पहली फिल्म-2
16. चेहरा,शक्ल-3
18. चाकू,खंजर-3
20. उक

भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की बढ़त हासिल की

बुमराह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

पर्थ (ईएमएस)। भारतीय टीम ने यहां पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम को 295 रनों से हराकर पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में उतरी भारतीय टीम ने इस मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी सहित हर क्षेत्र में कंगारुओं को पीछे छोड़ दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने जीत के लिए 534 रनों का लक्ष्य दिया था जिसका पीछा करते हुए मेजबान टीम चौथ दिन अपनी दूसरी पारी में 238 रनों पर ही आउट हो गयी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 89 रन ट्रेविस हेड ने बनाए। उनके अलावा मिचेल मार्श ने 47 रन बनाये पर अन्य बल्लेबाज असफल रहे। भारत की ओर से बुमराह ने 3 और मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट लिए जबकि वाशिंगटन सुंदर ने दो, हर्षित राणा और नीतिश रेड्डी ने एक-एक विकेट लिया।। इस मैच में भारतीय टीम की जीत में यशस्वी जायसवाल 161 और विराट कोहली 100 के अलावा केएल राहुल की 77 रन की अर्धशतकीय पारी की अहम भूमिका रही। इससे भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 487 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का विशाल लक्ष्य दिया। जिसके सामने मेजबान टीम ढ़ह गयी। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में ऋषभ पंत (37) और नितीश रेड्डी (41) की बदौलत 150 रन बनाए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अच्छी रही और जोश हेजलवुड ने 4 जबकि मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और मिशेल मार्श ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद जवाब में मेजबान टीम भी 104 पर सिमट गय। इस प्रकार पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को 46 रन की बढ़त बनाई। भारत की ओर से बुमराह के 5 विकेट शामिल थे। दूसरी इनिंग में यशस्वी यशस्वी और विराट के शतकों के अलावा केएल राहुल की 77 रन की अर्धशतकीय पारी से भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 487 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का विशाल लक्ष्य दिया। दूसरी पारी में भारत ने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने में बेहतर वापसी की। तीसरे दिन के तीसरे सत्र में ही 12 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। चौथे दिन की शुरुआत में ही मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को पंत के हाथ कैच आउट कराकर एक बड़ा झटका दिया। ख्वाजा ने इस पारी में 4 रनों का योगदान दिया।

इसके बाद मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने एक साझेदारी बनाने की कोशिश की और दोनों ने टीम का स्कोर 79 तक पहुंचाया। लंच से पहले भारत को एक और बड़ी सफलता तक मिली जब सिराज ने स्मिथ को 17 रनों पर आउट कर दिया। स्टीव स्मिथ ने आउट होने से पहले 60 गेंदों का सामना किया और एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इसी बीच ट्रेविस हेड के तेज अर्धशतक के चलते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा लेकिन लंच तक उनकी आधी टीम केवल 104 रनों के स्कोर पर ही आउट हो चुकी थी।

लंच के बाद हेड ने अपनी पारी को गति के साथ आगे बढ़ाना जारी रखा और कुछ शानदार शॉट्स खेले। हेड को 89 रनों के निजी स्कोर पर बुमराह ने पेवेलियन भेज दिया। हेड ने 101 गेंदों पर 8 चौके लगाए। इसके बाद नीतिश रेड्डी ने मिशेल मार्श को 47 रनों की पारी का अंत कर दिया।

इसके बाद सिर्फ विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ही निचले क्रम पर भारतीय गेंदबाजी का प्रतिरोध कर सके, जबकि दूसरे छोर पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। वाशिंगटन सुंदर ने मिशेल स्टार्क (12) और नाथन लियोन (0) के विकेट हासिल किए। वहीं, हर्षित राणा ने कैरी को बोल्ड करके विजयी विकेट हासिल किया। कैरी ने 58 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली।

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को तीन-तीन विकेट मिले। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को मैच में कुल आठ विकेट लेने के चलते प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया। बुमराह ने पहली पारी में भी पांच विकेट लिए थे। इस मैच से पदापर्ण करने वाले नीतिश रेड्डी ने भी मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन कर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

इंडोनेशिया में भूस्खलन और बाढ़ से 13 लोगों की मौत, 18 घायल

- आपदा डेली सरडांग और कारो क्षेत्रों में हुई

जकार्ता (ईएमएस)। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने 13 लोगों की जान ले ली और 18 लोग घायल हो गए। यह आपातकाल प्रबंधन एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया। उनके अनुसार यह आपदा डेली सरडांग और कारो क्षेत्रों में हुई। डेली सरडांग में तेज बहाव ने चार घरों और एक धार्मिक स्थल को बहा दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। कारो क्षेत्र में 7 लोगों की जान गई और 9 घायल हुए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। भूस्खलन और बाढ़ ने पडांग लावास और दक्षिण तपनुली क्षेत्रों को भी प्रभावित किया, जिसमें 6 लोग मारे गए और 7 घायल हुए। मौसम और भूभौतिकी एजेंसी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि क्षेत्र में भारी बारिश और खराब मौसम का खतरा है। प्रभावित समुदायों को सहायता पहुंचाने और आगे के जोखिम को कम करने के लिए प्रयास जारी है। अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सहायता कार्य जारी है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 992 , निफ्टी 314 अंक ऊपर आया

निवेशकों को 7 लाख करोड़ रुपये का लाभ

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार सोमवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आया है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा गठबंधन की जीत से भी निवेशकों का भरोसा बना है जिससे बाजार को बल मिला। इससे एक ही दिन में 7 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

आज कारोबार के दौरान रिलायंस, एचडीएफसी बैंक के शेयर भी ऊपर आये।

दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स आज 1.25 फीसदी तकरीबन 992.74 अंक बढ़कर 80,109.85 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.32 फीसदी तकरीबन 314.65 अंक ऊपर आकर 24,221.90 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 43 के शेयर लाभ पर बंद हुए

आज कारोबार के दौरानप सेंसेक्स की कंपनियों में एलएंडटी का शेयर 4 फीसदी से अधिक ऊपर आया। वहीं भारतीय स्टेट बैंक, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर भी बढ़त पर बंद हुए।

वहीं दूसरी ओर जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, मारुति, एशियन पेंट्स और एचसीएल टेक के शेयर फिसलकर बंद हुए।

इससे पहले आज सुबह

बाजार में भारी तेजी देखी गई। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1200 से ज्यादा अंक चढ़ गया जबकि निफ्टी 24,300 के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत से निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला है। सेंसेक्स उछाल के साथ 80,193 अंक पर खुला और सुबह के कारोबार में 80,452 के हाईएस्ट लेवल को छू गया। इंट्राडे में सेंसेक्स में 1,355 अंक की बढ़त दर्ज की गई। इसी तरह निफ्टी-50 भी जोरदार उछाल के साथ 24,253.55 अंक पर खुला और ओपनिंग बेल के कुछ ही मिनटों के भीतर 24,330 के इंट्राडे हाई को छू लिया। इस दौरान निफ्टी में 400 से ज्यादा अंक तक उछाल आया।

सोना 1,089 रूपए सस्ता हुआ

नई दिल्ली(ईएमएस)। सोने और चांदी की कीमतों में बीते दिनों लगातार बढ़ोतरी के बाद सोमवार को गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,089 रुपए घटकर 76,698 रुपए पर आ गया है। शुक्रवार को इसके दाम 77,787 रुपए प्रति दस ग्राम थे। वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 1,762 रुपए घटकर 89,088 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले शुक्रवार को चांदी की कीमत 90,850 रुपए प्रति किलो थी। इस साल सोना 30 अक्टूबर को 79,681 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वहीं, चांदी 23 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी।

भारत और नॉर्वे के बीच टेपा समझौते पर हुई चर्चा

- व्यापारिक संबंधों को और प्रगति देने की योजना बनाई

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील भार्थवाल ने हाल ही में नॉर्वे का दौरा किया। उनका यह दौरा भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए देशों के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टेपा) लागू करने में तेजी लाने और 100 अरब डॉलर के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था। भार्थवाल का नॉर्वे दौरा भारत और ईएफटीए देशों के बीच टेपा समझौते को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए था। इस समझौते के तहत, भारत को ईएफटीए देशों के बाजारों में अपने उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए 99.6 प्रतिशत बाजार का अधिकार मिलेगा। इसमें गैर-कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर महत्वपूर्ण टैक्स छूट दी जाएगी। भारत ने ईएफटीए देशों को 82.7 प्रतिशत अपनी टैक्स लाइनों की पेशकश की है, जो ईएफटीए के निर्यात का 95.3 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है। भारत ने ईएफटीए के लिए 105 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है, जबकि नॉर्वे ने 114 क्षेत्रों में प्रतिबद्धता की है। भार्थवाल ने नॉर्वे में टॉमस नॉर्वोल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इन बैठकों में मुख्य रूप से व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन देना, और टेपा के अनुमोदन में तेजी लाने के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा वाणिज्य सचिव ने नॉर्वेजियन संसद के सदस्यों से भी मुलाकात की और समझौते के संभावित लाभों पर जोर दिया।

सोना और चांदी के भाव में नरमी

- सोने का भाव 76,600 रुपए, चांदी 89,500 रुपए के करीब

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत में नरमी देखी जा रही है। सोमवार को दोनों के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 76,600 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 89,500 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सुस्त शुरुआत के बाद सोने-चांदी की वायदा कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 616 रुपये की गिरावट के साथ 77,000 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 1,043 रुपये की गिरावट के साथ 76,573 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत भी सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 435 रुपये की गिरावट के साथ 90,333 रुपये पर खुला। इस समय यह 1,345 रुपये की गिरावट के साथ 89,423 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव में नरमी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना 2,716.89 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,712.20 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 41.10 डॉलर की गिरावट के साथ 2,671.10 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 31.40 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 31.33 डॉलर था। इस समय यह 0.50 डॉलर की गिरावट के साथ 30.83 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

पाकिस्तान में शिया-सुन्नी समुदाय सीजफायर पर सहमत

-7 दिन तक रहेगा संघर्ष विराम, हिंसा में 64 लोगों की जान गई

इस्लामाबाद(ईएमएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जारी संघर्ष के बीच 7 दिन के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। सरकारी कोशिशों के बाद आपस में लड़ रही दोनों जनजातियां इसके लिए तैयार हो गई। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने दोनों समुदायों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय आयोग बनाने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार के प्रवक्ता मुहम्मद अली सैफ ने बताया कि सरकार ने दोनों समुदायों के नेताओं से बात की है। जिसके बाद सात दिन के संघर्ष विराम और एक-दूसरे को शव और बंदी लौटाने पर सहमति बनी।

पिछले हफ्ते इस संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में अलीजई (शिया) और बागान (सुन्नी) जनजाति के संघर्ष में पैसेंजर वैन काफिले पर फायरिंग की गई। ये सभी गाड़ियां एक काफिले में पारचिनार से खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर जा रही थी। दोनों समुदायों के बीच तीन दिन चली इस हिंसा में अब तक 64 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मरने वाली संख्या 100 से भी ज्यादा बताई जा रही है।

हिंद महासागर में दो नौकाओं के पलटने से 24 लोगों की मौत: सोमालिया सरकार

मोगादीशू (ईएमएस)। हिंद महासागर में मेडागास्कर तट के पास दो नौकाओं के पलटने से 24 लोगों की मौत हो गई। सोमालिया सरकार ने इसकी जानकारी दी। सोमालिया के विदेश मंत्री अहमद मोआलिम फिकी ने कहा कि 46 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश यात्री सोमालिया के युवा थे। इथियोपिया में सोमालिया के राजदूत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नौकाओं के पलट जाने घटना की जांच करने लिए सोमवार को मेडागास्कर जाएगा।

मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ने लगा तनाव, ईरान कर रहा जवाबी हमले की तैयारी

तेहरान(ईएमएस)। ईरान और इजरायल के बीच का तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में यह तनाव मिडिल ईस्ट के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरान लगातार इजरायल को धमका रहा है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी ने रविवार को एक इंटरव्यू में इजरायल को धमकी दी। उन्होंने कहा कि हाल में इजरायल के हमले का वह जवाब देने को लिए ईरान तैयारी कर रहा है। 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। इसमें मिसाइल उत्पादन स्थलों, एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु सुविधाओं सहित ईरानी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया था।

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये हमले ईरान की ओर से इजरायली सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर लॉन्च की गई 200 मिसाइलों के प्रतिशोध में था। इजरायल की एयर स्ट्राइक में ईरान को भारी नुकसान हुआ। कथित तौर पर हमलों में एडवांस्ड मिसाइल उत्पादन फैसिलिटी और रूस द्वारा निर्मित एस-300 वायु रक्षा प्रणाली सहित ईरान की सैन्य क्षमताओं को नुकसान हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बहाल करने में एक साल का समय लगेगा। ईरान ने पहले इजरायल के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई थी। लारिजानी का बयान दोनों देशों के बीच बढ़े हुए तनाव को दिखाता है। इस बीच हिजबुल्ला ने रविवार को इजराइल पर लगभग 250 रॉकेट और अन्य हथियारों से हमला किया जिससे कम से कम सात लोग घायल हो गए। यह हिजबुल्ला का पिछले कई महीनों में किया गया सबसे भीषण हमला है क्योंकि कुछ रॉकेट इजराइल के मध्य में स्थित तेल अवीव क्षेत्र तक पहुंच गए। इजराइल की मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने कहा कि उसने हिजबुल्ला की ओर से इजराइल पर दागे गए हमलों में घायल हुए सात लोगों का इलाज किया।

लेबनान के सैनिक की मौत

युद्ध विराम के लिए वार्ताकारों की ओर से दबाव बनाए जाने के बीच हिजबुल्ला ने ये हमले बेरूत में घातक इजराइली हमले के जवाब में किये। इसी बीच लेबनान की सेना ने कहा कि इजराइल के हमले में रविवार को लेबनान के एक सैनिक की मौत हो गई जबकि 18 अन्य घायल हो गए। इस घटना पर इजराइल की सेना ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमला हिजबुल्ला के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में किया गया और सेना का अभियान केवल चरमपंथियों के विरुद्ध हैं। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइली हमलों में 40 से अधिक लेबनानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि लेबनान की सेना इस युद्ध से मौटे तौर पर दूर रही है।

हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

-इजराइल ने हमलों में मारने वालों की संख्या और नुकसान की नहीं दी जानकारी

तेल अवीव ,(ईएमएस)। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की खबरों के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इजराइल सरकार की ओर से रविवार को हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या और नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है।

हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइली राजधानी तेल अवीव में खुफिया ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इजराइली पुलिस के मुताबिक तेल अवीव के पूर्वी हिस्से में हमले हुए हैं। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने तेल अवीव और आसपास के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। हिजबुल्लाह का यह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले एक सप्ताह से जारी इजराइली हमलों का जवाब है।

हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइली टैंकों को पीछे हटना पड़ा हिजबुल्लाह का हमला इतना भयानक और जोरदारर था कि इजराइली टैंकों और सैनिकों दक्षिणी लेबनान के अल-बयादा क्षेत्र में एक पहाड़ी से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। हिजबुल्लाह ने कई टैंक रोधी मिसाइलों से भी हमला किया था। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर के पास इजराइली मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पहली बार दक्षिणी इजराइल में अशदोद नौसैनिक बेस पर ड्रोन से हमला किया। ईरान ने भी इजराइल पर हमले की धमकी दी है।

कर्ज में डूबे अमेरिका की बढ़ी चिंता,मस्क बोले- दिवालिया होने की कगार पर सुपर पॉवर

वाशिंगटन(ईएमएस)। हर एक अमेरिकी नागरिक पर एक लाख डॉलर से अधिक का कर्ज है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) के मुताबिक, अमेरिकी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 4.47 खरब डॉलर का राजस्व कमाया। जबकि उसने 6.16 खरब डॉलर खर्च किए। जिसके नतीजे में 2.31 खरब डॉलर का घाटा हुआ। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में डीओजीईने खुलासा किया कि अमेरिका पर कर्ज केवल चार महीनों में 1 खरब डॉलर बढ़ गया है, जिससे वित्तीय अस्थिरता की चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका पर इस वक्त 36 खरब डॉलर से अधिक का कर्ज हो गया है। इसे लेकर टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी दी कि अमेरिका दिवालिया होने की कगार पर है। उनका बयान ऐसे समय में आया है, जब देश के बढ़ते कर्ज के बारे में चर्चा तेज हो गई है। यह कर्ज का बोझ अमेरिकी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

सरकारी दक्षता विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ने 2001 के बाद से बजट अधिशेष नहीं देखा है और इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया। इस डेटा पर टिप्पणी करते हुए एलन मस्क ने कहा कि 'अमेरिका तेजी से दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है।' उनका बयान अमेरिका की राजकोषीय नीतियों की स्थिरता के बारे में बढ़ती चिंताओं को दिखाता है, जिसमें अब हर अमेरिकी नागरिक पर 100,000 डॉलर से अधिक का कर्ज का बोझ है।

बढ़ते कर्ज संकट को रोकने लिए डोनाल्ड ट्रंप ने डीओजीई के जरिये सरकारी खर्च में 500 अरब डॉलर की कटौती करने की योजना को सामने रखा है। एलन मस्क और उद्यमी विवेक रामास्वामी की अगुवाई वाले विभाग को स्वास्थ्य सेवा, बच्चों के अनुदान और नासा के बजट सहित कई क्षेत्रों में खर्च को कम करने का काम सौंपा गया है।

नेपाल का व्यापार घाटा 460 अरब के पार

काठमांडू (ईएमएस)। नेपाल का व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले चार माह में 460 अरब रुपये से अ?धिक हो गया है। सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार नेपाल ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान 513.38 अरब रुपये के सामान का आयात किया, जबकि निर्यात केवल 52.67 अरब रुपये तक ही रहा। विभाग के अनुसार नेपाल ने चार महीनों में कुल 566.5 अरब रुपये के विदेशी व्यापार में 460.71 अरब रुपये का व्यापार घाटा देखा। आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में आयात 0.17 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निर्यात में 4.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में नेपाल का भारत के साथ व्यापार घाटा 281 अरब रुपये को पार कर गया है। इस अवधि के दौरान नेपाल ने भारत से करीब 317 अरब रुपये का सामान आयात किया, जबकि उसने भारत को सिर्फ 36 अरब रुपये का सामान निर्यात किया। इन चार महीनों में नेपाल ने 29.4 अरब रुपये का डीजल, 21.56 अरब रुपये का पेट्रोल और 18.85 अरब रुपये का एलपीजी आयात किया।

यूक्रेन का दावा - ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल के हमले में 500 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए

कीव (ईएमएस) । यूक्रेन ने दावा किया है कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल के हमले में 500 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। इस हमले में एक रूसी जनरल समेत 18 अन्य सैन्य अधिकारियों की भी मौत हुई है। पहले यह दावा किया गया था कि इन हमलों में उत्तर कोरियाई सेना के एक शीर्ष जनरल भी घायल हुए हैं। यह जनरल रूस के कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के आक्रामक अभियान की कमान संभाल रहे थे। यूक्रेनी सेना ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यह हमला 20 नवंबर को किया गया था।

इससे पहले यह जानकारी सामने आई थी कि यूक्रेनी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने एक रूसी कमांड पोस्ट और एक मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया था। तब इतना बताया गया था कि इस हमले में रूसी सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। मारे गए रूसी जनरल का नाम लेफ्टिनेंट-जनरल वालेरी सोलोडचुक था। रूसी अधिकारियों ने नुकसान की पुष्टि नहीं की है जिसे रूस और उत्तर कोरिया दोनों के लिए गंभीर बताया जा रहा है।

स्टॉर्म शैडो को कुर्स्क क्षेत्र में एक ज़ारिस्ट एस्टेट पर मैरीनो में एक भूमिगत सैन्य सुविधा पर निशाना बनाया गया था। नए फुटेज में हमले में शामिल स्टॉर्म शैडो मिसाइल को दिखाया गया है, जो अपने लक्ष्य की ओर उड़ रही थी। हालांकि, रूस की चुप्पी होने और किसी स्वतंत्र सूत्र से पुष्टि न होने के कारण यूक्रेन के इस दावे पर संदेह भी जताया जा रहा है। हमला जिस इलाके में हुआ है, उस क्षेत्र में 10 हजार से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात हैं।

ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस भारी नुकसान के कारण ही यूक्रेन पर एक नई मिसाइल से हमला बोला था। रूस ने इसी स्टॉर्म शैडो मिसाइळ के हमले के बाद यूक्रेन के नीपर पर एक नई ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी। इसके बाद पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि उनके पास एक नया सुपर हथियार है जिसे पश्चिम रोक नहीं सकता। मॉस्को ने यह भी धमकी दी कि यूक्रेन द्वारा नाटो द्वारा आपूर्ति की गई मिसाइलों का उपयोग करने का मतलब है कि पुतिन वैध रूप से परमाणु मिसाइलों से जवाबी हमला कर सकते हैं।

इजराइल ने बेरुत में हिजबुल्लाह कमांड सेंटरों को बनाया निशाना, 29 लोग मारे गए

बेरूत (ईएमएस)। इजराइल ने फिर बेरूत को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने बेरूत और उसके दक्षिणी उपनगरों पर कई हवाई हमले किए हैं। इसके पहले इजरायल ने लेबनान की राजधानी को निशाना बनाया था, जिसमें करीब 29 लोग मारे गए थे और 66 अन्य घायल हो गए थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने बेरूत के हिजबुल्लाह कमांड सेंटरों पर खुफिया जानकारी के आधार पर हमले किए है, जिसमें हरेत हरेक, बुर्ज बरजनेह और हदथ जैसे इलाके शामिल थे। साझा किए गए फुटेज में दक्षिणी उपनगरों के ऊपर काले धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमले शनिवार को बेरूत के बस्ता फावका इलाके में एक आठ मंजिला आवासीय इमारत पर हुए घातक हमले के बाद किए गए हैं।

इस बीच, इजरायली मीडिया ने बताया कि इस हमले में हिजबुल्लाह के एक प्रमुख अधिकारी, लेबनानी सांसद और हिजबुल्लाह के सदस्य अमीन शेरी को निशाना बनाया गया। इजरायल के हवाई हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने दक्षिणी लेबनान में पांच इजरायली टैंकों को नष्ट कर दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 8 अक्टूबर 2023 को संघर्ष शुरू होने के बाद से इजरायली हवाई हमलों में 3,754 लोग मारे गए हैं और 15,626 घायल हुए हैं।

मकान पर गिरा डीएचएल का मालवाहक विमान, एक की मौत, एक घायल

लीपजिंग,(ईएमएस)। पार्सल एवं कूरियर सेवा देने करने वाली जर्मनी की कंपनी डीएचएल का एक मालवाहक विमान सोमवार सुबह लिथुआनिया की राजधानी के पास एक मकान पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना में घायल दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया जबिक दूसरे का इलाज जारी है।

मीडिया रिपोर्ट में लिथुआनिया के आपातकालीन अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि

डीएचएल का मालवाहक विमान हवाई अड्डे के पास दो मंजिला मकान के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद दमकल गाड़ी सहित आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गईं। डीएचएल ग्रुप का मुख्यालय जर्मनी के बॉन में है। कंपनी ने घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। डीएचएल विमान का संचालन मैड्रिड स्थित 'स्विफ्टएयर' करती है। विमान वाहक कंपनी से तुरंत संपर्क नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि यह बोइंग 737 विमान 31 सालपुराना था, जिसे विशेषज्ञ विमान का पुराना ढांचा मानते है, हालांकि मालवाहक उड़ानों के लिए यह असामान्य नहीं है।

कई चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने इमरान ने बढ़ाई एक और मुसीबत

इस्लामाबाद(ईएमएस)। पाकिस्तान में एक के बाद एक नई नई चुनौतियां आ रहीं हैं। पहले आर्थिक फिर शिया सुन्नी झगड़ा और अब पूर्वे पीएम इमरान खान की पार्टी का प्रदर्शन सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में रविवार से पीटीआई का प्रदर्शन शुरू हो गया है। अलग-अलग इलाकों से पीटीआई के हजारों समर्थकों ने कूच करना शुरू कर दिया है। इस प्रदर्शन के शुरू होने से पहले ही 48 घंटे के लिए पूरे इस्लामाबाद में अघोषित लॉकडाउन कर दिया है। और शायद पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है, जिसकी राजधानी इस वक्त कंटेनर लॉक्ड है। पाकिस्तान सरकार ने इस प्रदर्शन को दबाने और इस्लामाबाद तक प्रदर्शनकारियों को ना पहुंचने देने के लिए जितने भी रास्ते हैं, सबको बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर रखकर बंद कर दिया है। कुल 35 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो बाकी प्रांत से इस्लामाबाद को जोड़ती हैं, जो बंद हैं। जिन शिपिंग कंटेनरों से सड़कें ब्लॉक की गई हैं, ये कोई मुफ्त की नहीं हैं। इसके लिए भी करोड़ों खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर ये प्रदर्शन लंबे समय तक चला तो इन कंटेनरों के लिए शहबाज सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कंटेनर के किराए की बात करें तो यह करोड़ों में है।

रिपोर्ट के मुताबिक, तकरीबन 25 करोड़ रूपये तो 1600 से ज्यादा का कंटेनरों के किराये के तौर पर पिछले पांच महीने में पाकिस्तानी सरकार को चुकाने पड़े हैं। और एक बार फिर से कंटेनर सड़कों पर हैं। पिछले डेढ़-दो साल में सरकार को प्रदर्शनों को रोकने के लिए 270 करोड़ रुपये ज्यादा का खर्च पड़े हैं। इस प्रदर्शन का कॉल इमरान खान ने जेल से किया। अपने सभी समर्थकों को इस्लामाबाद आने की अपील की। तीन मांगों को माने जाने त

वलसाडः छात्रा से दुष्कर्म मामला, 12 दिन बाद घटना स्थल से 18 किमी दूर पकड़ा गया आरोपी

वलसाडः वलसाड में पारडी के मोतीवाला स्थित एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद जिला पुलिस तंत्र में हड़कंप मच गया. पूरी घटना में आरोपियों की तलाश के लिए जिला पुलिस ने 10 से ज्यादा टीमें गठित कीं. जिसमें जीआरपी टीम को पता चला कि आरोपी वापी रेलवे स्टेशन की पार्किंग में घूम रहा है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई की.

दुष्कर्म व हत्या मामले का आरोपी गिरफ्तार

वलसाड जिले के पारडी तालुका के मोतीवाला फाटक के पास रहने वाले एक परिवार की बेटी टयूशन जाने के बाद घर नहीं लौटी. पूरी घटना में बेटी का शव संदिग्ध हालत में मिला. जिसमें बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या किए जाने की बात सामने आने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाईं. जिसमें पुलिस द्वारा घटना स्थल से 18 कि.मी. मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले आरोपी को 12 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

कैसे पकड़ा गया आरोपी?

पुलिस को पहले सूचना मिली थी कि आरोपी हरियाणा का रहने वाला है और जांच में यह भी पता चला कि पहचान छिपाने के लिए खाली बैग और कपड़े रेलवे ट्रैक के पास फेंके गए थे. जिसके बाद पुलिस ने रेलवे ट्रैक और आसपास के पार्किंग कैमरों की फुटेज चेक की. जिसमें एक बैग लटकाए और कपड़े पहने नजर आ रहा था. पुलिस ने उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में वह टूट गया और जुर्म कबूल कर लिया।

आरोपी का आपराधिक इतिहास है

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि वह कई अपराधों में शामिल था. उसके खिलाफ पुलिस राज्यों में चोरी, डकैती, मारपीट के 10 से अधिक अपराध दर्ज हैं। आरोपी खासकर रात के समय ट्रेनों से यात्रियों का कीमती सामान चोरी करते थे। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने 10 हजार कीमत के विदेशी कंपनी के जूते पहने हुए थे. संदेह है कि उसने ये जूते ट्रेन से चुराए हैं।

क्या थी पूरी घटना?

वलसाड जिले के पारदी तालुका के मोतीवाला फाटक के पास रहने वाले एक परिवार की बेटी कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी. छात्रा 14 नवंबर को टयूशन के लिए गई थी, लेकिन जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की. जिसमें छात्र मोतीवाला फाटक के पास अंबावाड़ी में संदिग्ध हालत में मिला। इसके बाद परिजन बेटी को पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। जिसमें पता चला कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई.

वडोदरा में तस्करों ने वारसिया इलाके में एक सोसायटी के घर में चोरी का प्रयास किया

वड़ोदरा : वड़ोदरा के वारसिया रोड स्थित एक घर में चोरों ने चोरी का प्रयास किया. बुजुर्ग माता-पिता नीचे के कमरे में सो गए और बेटा दरवाजा बंद कर ऊपर सो गया। सुबह-सुबह नीचे के मकान का ताला टूटने की आवाज सुनकर दंपत्ति जगे और नीचे का दरवाजा खुला देख चीख पड़े। चोरी करने आए तस्कर भाग गए। एक बार फिर पुलिस की रात्रि गश्ती की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं. घर का मालिक शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया लेकिन उसे बताया गया कि उसकी शिकायत दोपहर में ली जाएगी।

वडोदरा शहर में तस्कर विभिन्न घरों को ऐसे निशाना बना रहे हैं मानो वे बेखौफ हो गए हों. शहर पुलिस की रात्रि गश्ती की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है. एक बार फिर पुलिस की नाकामी सामने आ रही है. वडोदरा के वारसिया रिंग रोड पर शांति सोसायटी के मकान नंबर 22 में रहने वाले परेशभाई राणा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऊपर सो रहे थे। जबकि उसके वृद्ध माता-पिता जमीन चार पर सोते थे। परेशभाई खुद ही घर का दरवाज़ा बाहर से बंद करके ऊपर चले जाते थे ताकि उनके माता-पिता को सुबह नींद से न जागना पड़े। इस दौरान। 25 नवंबर को सुबह 5:30 से 6:00 बजे के बीच उन्हें अपने ग्राउंड फ्लोर के भवन के दरवाजे का ताला टूटने की आवाज सुनाई दी. तो दंपत्ति जाग गए और दरवाजा खुला देखकर चिल्लाए, इसी दौरान पड़ोसी भी जाग गए और चोरी करने आए तस्कर भाग गए। बेटे-बहू के जाग जाने से माता-पिता बच गये। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जब परेशभाई थाने में शिकायत दर्ज कराने गए तो शिकायत नहीं ली गई और उन्हें दोपहर में बुलाया गया.

राष्ट्रीय दुग्ध दिवसः वडोदरा जिले की 680 दुग्ध समितियों से जुड़े 104613 पशुपालक, प्रतिदिन 5.83 लाख किलो दूध की आय

वडोदराः दूध के बिना एक भी दिन नहीं गुजरता जो दैनिक आहार शैली का अभिन्न अंग है। पशुपालक वडोदरा शहर और जिले के नागरिकों की दैनिक दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं और वडोदरा डेयरी के माध्यम से सभी तक दूध पहुंचाया जाता है। वडोदरा में प्रतिदिन 5.83 लाख किलोग्राम दूध एकत्र किया जाता है और उचित प्रसंस्करण के बाद इसे घर-घर पहुंचाया जाता है। 26 तारीख को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर कुछ विवरण जानना दिलचस्प होगा।

भारतीय श्वेत क्रांति के प्रणेता डॉ. वर्गीस कुरियन की जयंती 26 नवंबर को हर साल डेयरी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करने के लिए 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' मनाया जाता है। यह खास दिन देश के डेयरी और सहकारी क्षेत्रों की उपलब्धियों को गौरवान्वित करने का दिन है।

वडोदरा जिले की बात करें तो वर्ष 2023-24 के दौरान जिले की दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा कुल 11.53 करोड़ लीटर से अधिक दूध एकत्र किया गया है। इसी अवधि तक जिले की 680 दुग्ध समितियों से 104613 पशुपालक जुड़े हुए हैं।

राज्य सरकार द्वारा उठाये गये ठोस कदमों तथा पशुपालन से संबंधित योजनाओं के सुदृढ़ क्रियान्वयन से दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 तक वडोदरा डेयरी द्वारा एकत्रित आंकड़े क्रमशः 4.53 लाख किलोग्राम, 4.73 लाख, 5.85 लाख, 6.52 लाख, 6.49 लाख, 7.12 लाख, 6.24 लाख, 6.15 लाख, 6.66 लाख, 6.03 हैं। इस दशक में लाख किलो दूध एकत्र किया गया था वर्ष 2023-24 में वडोदरा शहर में 5.83 लाख किलो दूध आया है. उप पशुपालन निदेशक डॉ. धवल मांडविया ने कहा.

क्या आप यह जानने को उत्सुक हैं कि इतना दूध कहां से आता है? तो इसका उत्तर यह है कि वडोदरा डेयरी में सबसे ज्यादा दूध प्रतिदिन 9463 किलो दूध तिलकवाड़ा के वोरा गांव से आता है। इसी तरह, जेतपुर पावी तालुक के वानकी गांव से 8511 किलोग्राम दूध और वाघोडिया के शंकरपुरा गांव से 3392 किलोग्राम दूध प्रतिदिन वडोदरा आता है।

शुपालन को अब एक व्यवसाय के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। एक पशुपालक की आय जानकर आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी! तिलकवाड़ा तालुक के वोरा गांव के दानाभाई वाजेसिंह अम्बालिया सोसायटी में सालाना 82187 किलोग्राम भैंस का दूध दुहते हैं और 46.24 लाख रुपये कमाते हैं। आईआईटी-मुंबई से पढ़ाई के बाद भी नहीं मिलता इतनी रकम का पैकेज!

वडोदरा जिले में सबसे अधिक आय पादरा तालुक के गमेथा गांव के चरवाहे घनश्यामभाई रणछोड़भाई पढियार को होती है। उनके पास 25 भैंस और 15 गाय हैं। वे सालाना 26411 किलो भैंस का दूध और 20523 किलो गाय का दूध पैदा करते हैं। इससे उन्हें सालाना 21.63 लाख रुपये की आय होती है.

किसानों से कृषि भूमि छीनने की नींव मोदी ने तब रखी थी जब वह अक्टूबर 2001 को राज्य के मुख्यमंत्री बने थे : कांग्रेस

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात राज्य निर्यात निगम को बेच दिया गया, गुजरात राज्य भूमि उपयोग निगम और गुजरात भूमि विकास निगम पर ताला लगा दिया गया, गुजरात राज्य बीज निगम और गुजरात राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी मृत्यु शैया पर, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज़ के सभी कृषि इनपुट का उत्पादन बंद कर केवल नोडल एजेंसी बनाया दिया गया है यह गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मनहर पटेल ने लगाए हैं यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस प्रवक्ता मनहर पटेल ने बताया कि गुजरात के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विभागों में कर्मचारियों/ अधिकारियों के 50 से 80ः पद खाली हैं, जिससे साबित होता है कि 24 वर्षों में राज्य सरकार ने किसानों के लिए इनमें से एक भी सरकारी उद्यम चलाने पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जहां करोड़ों रुपये की लागत से कृषि अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, के 5 महाविद्यालयों में प्राचार्य नहीं हैं और शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के लिए वर्ग 1 और 2 के कुल 80 पद रिक्त हैं जिनमें 20 में से 19 महत्वपूर्ण हैं कृषि विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्षों यानी प्रोफेसरों के पद खाली हैं ऐसे में यह आसानी से समझा जा सकता है कि इस कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा कार्य में कितनी गति आ सकती है और इसमें कितनी गुणवत्ता पाई जा सकती है? ऐसा ही राज्य के कृषि विभाग का हाल, राज्य के कृषि विभाग के प्रमुख का पद 3 साल से अस्थायी तौर पर है और आज भी खाली हैं यह सीधा संकेत है कि राज्य सरकार को कृषि या किसानों की सेवा में कोई रुचि नहीं हैं 1990 में 356 स्वीकृत सीटें थीं जिनमें से 233 सीटें भरी हुई थीं जबकि 2021 में स्वीकृत सीटें घटकर 204 हो गईं और 104 रिक्तियां भी थीं, आज 2024 में हमारी जानकारी के अनुसार केवल 56 सीटें ही भरी हैं। इस प्रकार, भाजपा सरकार ने गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के कार्यालय को शून्य कर दिया जिससे पता चलता है कि राज्य सरकार किसान और कृषि के प्रति कितना सम्मान करती है गुजरात राज्य बीज निगम पर ताला लगाकर किसानों के बीज का मामला निजी बीज उत्पादकों को सौंप दिया है। इसके साथ ही गुजरात राज्य बीज प्रमाणपत्र एजेंसी का भी यही हाल है जहां एक समय में 400 कर्मचारी/अधिकारी की जगह आज 3 हैं ऐसे कई कारण हैं जो किसानों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। हमारा लगातार यही कहना रहा है कि कृषि हर उद्योग का कच्चा माल पैदा करती है और अगर हम कृषि को खत्म कर देंगे तो उद्योग कैसे बचेंगे? पूरे भाजपा परिवार और सरकार को सदबुद्धि मिलें

अभिभावकों के लिए चेतावनीः ऐसे स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया से पहले सोचें जो प्रवेश के लिए विज्ञापन देता हो

वडोदरा : विभिन्न स्कूलों में इस समय अगले शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है. कई स्कूल एडमिशन प्रक्रिया के लिए तरह-तरह का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. केवल उन्हीं स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से विज्ञापन देना होगा जिनकी कक्षाओं में सभी सीटें नहीं भरती हैं। इसलिए ऐसे स्कूल में एडमिशन लेने से पहले माता-पिता को एक बार सोचना चाहिए!

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए इस समय सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। अधिकांश स्कूलों ने प्रवेश प्रक्रिया के लिए अभिभावकों को पहले ही अपने संदेश भेज दिए हैं। चूँकि कई स्कूल प्रवेश प्रवेश के अनुसार पूर्ण प्रवेश नहीं भरते हैं, ऐसे स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार स्टंट का सहारा लेना पड़ता है। जिन विद्यालयों में पूर्ण नामांकन नहीं भरा है, वहां विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता अथवा यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों पर सवाल उठने की चर्चा शैक्षिक क्षेत्र में कहीं न कहीं होती रहती है। जो स्कूल स्वयं बच्चों का पूर्ण नामांकन नहीं करते उन्हें प्रवेश के लिए भारी विज्ञापन देना पड़ता है। कई स्कूल ज़ेरॉक्स जैसे प्रवेश फॉर्म के लिए 100 रुपये से अधिक शुल्क लेते हैं और प्रवेश प्रक्रिया को लंबा खींचकर अभिभावकों से खुलेआम पैसे वसूलते हैं। लेकिन इस मामले में कोई भी नेता या छात्र नेता एक शब्द भी नहीं बोलता. ऐसे स्कूलों के खिलाफ सकारात्मक रुख दिखाने से अभिभावकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.

कुछ स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया बहुत कुशल नहीं है क्योंकि वे प्रवेश प्रक्रिया जल्दी पूरी कर लेते हैं और माता-पिता अक्सर प्रवेश या प्रवेश शुल्क के तुरंत भुगतान के लिए दबाव डालते हैं। माता-पिता को एडमिशन के तहत फॉर्म एक से अधिक स्कूलों में जमा करना होगा ताकि उनके बच्चे का शैक्षणिक वर्ष खराब न हो। फिर जिस स्कूल का प्रदर्शन ख़राब होता है वहां एडमिशन प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है. फिर ऐसे स्कूल अभिभावकों से तुरंत पैसा वसूल कर उन्हें प्रवेश शुल्क वापस नहीं करते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जहां शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया अधिक कुशल है और इसके शिक्षक भी अच्छे हैं जहां माता-पिता प्रवेश के लिए लाइन में लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया का विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है। माता-पिता को अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या प्रवेश लेना चाहिए? इस स्तर पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है.

राज्य सरकार या डीईओ हर स्कूल को एक साथ प्रवेश प्रक्रिया क्यों नहीं करा सकते?

फिलहाल ज्यादातर स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है. जबकि खराब प्रदर्शन वाले कुछ स्कूल प्रवेश प्रक्रिया में देरी करने के लिए जाने जाते हैं और जहां सारा और उनके शिक्षक गुणवत्तापूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, वहां प्यार की कमी के कारण प्रवेश के लिए लंबी कतारें लगती हैं। अधिकांश समय प्रवेश पूरे नहीं होते हैं, स्कूल प्रारंभिक प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करते हैं। माता-पिता अच्छे दूसरे स्कूल में प्रवेश की पुष्टि होने की प्रतीक्षा करने के लिए उत्सुक हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि माता-पिता को वहां प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जहां उन्होंने प्रारंभिक प्रवेश प्रक्रिया पूरी की है और बाद में जहां वे चाहते हैं वहां प्रवेश लेने पर उन्हें पिछले स्कूल में भुगतान की गई प्रवेश शुल्क का रिफंड नहीं मिलता है। फिर स्कूलों का दलित यह है कि, 'यदि हम प्रत्येक अभिभावक को प्रवेश शुल्क की राशि वापस कर देंगे तो हमें आर्थिक रूप से नुकसान होगा और यदि अभिभावक बाद में प्रवेश के नाम कम कर देंगे तो प्रवेश का पूरा भुगतान नहीं किया जाएगा।' राज्य सरकार और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एक ही समय में सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने और छात्र की योग्यता घोषित करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाते? राज्य शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. जब अभिभावकों को भी स्कूल विभिन्न तरीकों से लूट रहा है तो यह जरूरी है कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए सरकारी तंत्र अभिभावकों को इस संबंध में कुछ राहत दे।

वडोदरा निगम का प्रशासन हर साल वार्ड नंबर 13 में बरसाती नाले के स्लैब को तोड़कर नया निर्माण कर देता है।

वड़ोदरा निगमः वड़ोदरा नगर निगम हर साल एक काम करता है और लोगों के लाखों टैक्स डॉलर बर्बाद कर देता है। इतना खर्च करने के बाद भी नतीजा शून्य ही रहता है. काम बरसाती नालों और उनके ऊपर बनी स्लैबों को तोड़कर साफ करना है। वार्ड नंबर 13 में हर साल बरसाती नाले पर बना स्लैब टूट जाता है. हर साल उस स्लैब की सफाई कर उसे ढक दिया जाता है। बरसात में जलभराव की समस्या के बाद बरसात खत्म होते ही यह फिर टूट जाता है।

वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के एक वरिष्ठ पार्षद के अनुसार, गंगोत्री पंच रोड के पास चौखंडी और श्रद्धा की ओर से आने वाले बरसाती नाले को ढकने वाला स्लैब, जो यहां बरसाती नाला बनाता है, हर बार टूट जाता है और हर बार नया स्लैब बना दिया जाता है। समय। पिछले साल भी बरसात में स्लैब टूट गया था और नया बना दिया गया था। जो इस बार फिर टूट गया है. हर साल एक ऑपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है। स्लैब तोड़ने से सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, लोगों का ध्यान भटक जाता है और असुविधा होती है। इस अकेले ऑपरेशन में लाखों लोगों के टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि मैं 14 साल से इस क्षेत्र का पार्षद हूं. थोड़ी सी बारिश में ही क्षेत्र में बारिश का पानी भर जाता है। बरसाती नाले ठीक नहीं होने के कारण पानी का निस्तारण नहीं हो पाता है। गला घोंटना। सफ़ाई करने का समय. इस मामले को कमिश्नर के समक्ष रखा जाएगा और जांच की मांग की जाएगी कि हर साल ऐसा क्यों होता है। एक ही काम पर पैसा क्यों खर्च करें? इसे इस तरह से किया जाए कि स्लैब को बार-बार न तोड़ना पड़े और लोगों का पैसा भी बर्बाद न हो।

मोरबी में सूदखोर ने युवक को ऑफिस में बुलाकर और रुपयों की मांग की और उसके साथ मारपीट की

मोरबीः पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है कि मोरबी के रावापार स्थित होटल फाइनेंस के कार्यालय में एक युवक को ब्याज दिया गया, कार्यालय में बुलाकर अधिक ब्याज की मांग की और मुझे घायल करने और जान से मारने की धमकी दी.

मोरबी के शनाला रोड पर धरती अपार्टमेंट में रहने वाले चिरागभाई महेशभाई गोस्वामी ने मोरबी डिवीजन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि चिराग ने आरोपी शिवम रबारी से ब्याज पर पैसे लिए थे, जिसके लिए चिरागभाई को शिवम रबारी के मोरबी स्थित होटल फाइनेंस कार्यालय में बुलाया गया था। उनसे बात करने के लिए रावापार रोड.

सड़क पर रईशजादे की कार का आतंक, शराब के नशे में पांच वाहनों को मारी टक्कर

अहमदाबाद (ईएमएस) शहर के बोपल-आंबली रोड पर शराब के नशे में धुत्त एक रईशजादे ने कई वाहनों को टक्कर मार दीं रईशजादा शराब के नशे में इतना धुत्त था कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं पा रहा था देर रात की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रईशजादे को पकड़ लिया और उसकी अच्छे से खातिरदारी कर दीं अहमदाबाद में रविवार की रात एक हिट एंड रन की घटना सामने आई। रईशजादे जब चार पहिया वाहन का स्टीयरिंग उनके हाथ में आ जाता है तो वह सड़कों पर चलने वालों को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं खासकर तब जब नशे में धुत्त हों तब ऐसे रईशजादे अन्य लोगों के लिए खतरनाक साबपित होते हैं शराब के नशे में धुत्त होकर फोर व्हील चलानेवाले रईशजादे एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि उनकी रफ्तार किसी और के लिए मौत की सजा बन सकती हैं अहमदाबाद सहित राज्य भर में लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं हैं ऐसे लोग एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं और ऐसे कभी कभार कार बेकाबू हो जाती है और हादसे हो जाते हैं जिसमें कई निर्दोष लोग शिकार बन जाते हैं, तो कुछ की जान भी चली जाती हैं अहमदाबाद में एक बार फिर ऐसी ही घटना घटी हैं जिसमें रिपल पंचाल नामक शख्स ने अपनी कार से पांच वाहनों को टक्कर मार दीं पांच गाड़ियों को टक्कर बाद इस रिपल पांचाल ने गाड़ी पास के डिवाइडर से टकरा गईं हालाँकि सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन कई बाइक और कारों परखच्चे उड़ गएं रिपल पंचाल नाम का यह शख्स इतना नशे में था कि वह ठीक से चल या बोल भी नहीं पा रहा था। इतने भयानक हादसे के बाद भी रिपल पंचाल कार में बैठकर शराब पीते हुए पकड़ा गया। एक्सीडेंट के बाद भी वह कार में बैठकर सिगरेट पीने लगा। गुस्साए लोगों ने उसे गाड़ी से खींच लिया और उसकी अच्छे से खातिरदारी कर दीं बोपल-अंबाली रोड पर हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी हैं आरोपी रिपल पांचाल सेनको वाल्व प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताया गया है। इतना ही नहीं जांच में पता चला है कि ऑडी कार सेनको वॉल्व प्राइवेट लिमिटेड रिपल पंचाल के नाम पर है। पुलिस ने हिट एंड रन मामले के आरोपी रिपल पांचाल का ब्लड सैंपल लिया हैं जानकारी के मुताबिक एफएसएल की टीम से जांच करायी जा रही हैं इसके साथ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस अलग से बनेगा।

27 और 28 नवंबर को रेलवे क्रॉसिंग नंबर 39 B (सोकली) बंद रहेगा

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद –विरमगाम सेक्शन पर जखवाड़ा-विरमगाम स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 39 B (सोकली) किमी. 553/34-36, मरम्मत एवं रखरखाव कार्य हेतु 27 नवंबर 2024 को प्रातः 08:00 बजे से 28 नवंबर 2024 को प्रातः 08.30 बजे तक बंद रहेगा।

इस अवधि के दौरान हल्के वाहन रेलवे क्रॉसिंग नं. 35 (विरोचन नगर) से एवं भारी वाहन रेलवे क्रॉसिंग नं. 37 (सचाना) से आवागमन कर सकते है।

11 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में शोक

राजकोट (ईएमएस) आए दिन हार्ट अटैक से मौतों की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई परिवारों ने दिल के दौरे में अपने परिजनों को खो दिया है। राजकोट में 11 साल के एक बच्चे की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई बच्चे के अचानक गिर जाने के बाद परिजनों द्वारा बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां अस्पताल में डयूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया जानकारी के मुताबिक राजकोट शहर के गोंडल रोड के पास विजय प्लॉट में रहने वाला 11 साल का देवराज कनकभाई करेलिया सुबह अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ बैठा था उस वक्त अचानक देवराज जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद देवराज के पिता ने हार्ट पंपिंग भी की और बाद में उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल में डयूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने देवराज को मृत घोषित कर दिया जानकारी के मुताबिक कनकभाई करेलिया के दो बेटे हैं। जिसमें देवराज बड़ा था और छठवीं कक्षा का छात्र था अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि देवराज की मौत हार्ट अटैक से हुई हैं

बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव ने कल्याण ज्वैलर्स के नए शोरूम का उद्घाटन किया

भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद आभूषण ब्रांडों में से एक, कल्याण ज्वैलर्स ने आज वडोदरा में अपना नया शोरूम लॉन्च किया, जो बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव द्वारा शहर में कंपनी के प्रवेश का प्रतीक है। शोरूम का उद्घाटन किया गया. कल्याण ज्वैलर्स के विभिन्न संग्रहों से डिजाइनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हुए, कल्याण ज्वैलर्स ने गुजरात राज्य में दस स्थानों पर अपनी उपस्थिति स्थापित की है। बॉलीवुड स्टार राजकुमार आवा ने कहा कि कल्याण आज यहां उद्घाटन के लिए उपस्थित होकर खुश हैं कल्याण ज्वैलर्स का नया शोरूम। ज्वैलर्स का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात है, एक ऐसा ब्रांड जो विश्वास, पारदर्शिता और ग्राहक केंद्रितता के सिद्धांतों पर मजबूत है, कंपनी के नए शोरूम के बारे में जहां संग्रह देखा जा सकता है, कल्याण ज्वैलर्स के कार्यकारी निदेशक श्री रमेश कल्याण रमन ने कहा एक कंपनी के रूप में हम हम

महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गए हैं और ग्राहकों के खरीदारी अनुभव को बढ़ाने के लिए एक व्यापक इको-सिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। पिछले कुछ वर्षों में हमने रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है और हमें विश्वास है कि वडोदरा में शोरूम हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा। बाजार की स्थिति और हमारे मूल्यवान ग्राहकों को अधिक लचीलापन और पहुंच प्रदान करेगी

एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया 'एक्सिस मोमेंटम फंड'

हाल के वर्षों में एक निवेश रणनीति के रूप में मोमेंटम इनवेस्टमेंट ने भारत में महत्वपूर्ण रफ्तार हासिल की है, क्योंकि निवेशक तेजी से देश की गतिशील अर्थव्यवस्था के भीतर बाजार के रुझान और विकास के अवसरों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यवहार का लाभ उठाने के लिए, भारत के सबसे तेजी से बढ़ते फंड हाउसों में से एक एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस मोमेंटम फंड पेश किया है। यह मोमेंटम थीम का पालन करने वाली एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है। एक मजबूत ढांचे के लिए एक संरचित और मॉडल-आधारित दृष्टिकोण के साथ, योजना का निवेश उद्देश्य मोमेंटम थीम के आधार पर इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो से निवेशकों के लिए दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर उत्पन्न करना है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि योजना का निवेश उद्देश्य हासिल किया जाएगा।

एक्सिस मोमेंटम फंड के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ श्री बी गोपकुमार ने कहा, ''भारत की उभरती अर्थव्यवस्था उन लोगों के लिए अलग-अलग अवसर प्रस्तुत करती है जो बाजार के रुझानों का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकते हैं। मोमेंटम निवेश, एक ऐसी रणनीति है, जिसे वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से अपनाया गया है। यह रणनीति भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ तेज़ी से क्षेत्रीय बदलाव और विकसित होते बाजार की गतिशीलता निरंतर बेहतर प्रदर्शन के अवसर पैदा करती है। इसी दौर में एक्सिस मोमेंटम फंड को लॉन्च करना दरअसल निरंतर इनोवेशन करने और निवेशकों को अत्याधुनिक निवेश रणनीतियों तक पहुँच प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। हमारा यह कदम विकसित होते बाजार की गतिशीलता के साथ जुड़ा हुआ है। मोमेंटम निवेश की शक्ति का उपयोग करके, हमारा लक्ष्य विकास के नए रास्ते खोलना है, जो हमारे निवेशकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है।

मोमेंटम निवेश को समझना

मोमेंटम निवेश, एक रणनीति के रूप में मजबूत ऊपर की ओर रुझान वाली अंतर्निहित प्रतिभूतियों की पहचान करने और उनका पूंजीकरण करने पर केंद्रित है। कम मूल्य वाले स्टॉक या उच्च-विकास वाली कंपनियों की तलाश करने के सामान्य दृष्टिकोण के विपरीत, मोमेंटम निवेश 'उच्च स्तर पर खरीदने के लिए उच्च स्तर पर बेचने' के सिद्धांत को अपनाता है। जबकि अक्सर सरलीकृत, मोमेंटम निवेश कठोर मात्रात्मक विश्लेषण पर आधारित है। मजबूत फ़िल्टर लागू करके, मजबूत प्रदर्शन संकेतकों वाले स्टॉक की स्क्रीनिंग की जाती है, जिससे यह अलग-अलग बाज़ार स्थितियों के अनुकूल हो जाता है और निर्णय लेने पर भावनात्मक पूर्वाग्रहों के प्रभाव को कम करता है। भारत में, मोमेंटम निवेश ऐतिहासिक प्रदर्शन डेटा से लाभान्वित होता है, जिसमें निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जैसे मोमेंटम इंडेक्स अक्सर जोखिम-समायोजित आधार पर व्यापक बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।एक्सिस मोमेंटम फंडएक्सिस मोमेंटम फंड एक अद्वितीय मॉडल-आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्च-गति वाली प्रतिभूतियों की व्यवस्थित रूप से पहचान करता है और उनमें निवेश करता है। फंड एक ऐसा ढांचा अपनाता है जो डेटा उपलब्धता और तरलता पर विचार करके प्रतिभूतियों को फ़िल्टर करता है, और फिर मूल्य गति रुझानों के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। अनिवार्य रूप से, पोर्टफोलियो निर्माण के दौरान एक अनुकूलित प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जो समग्र रैंक, स्टॉक के जोखिम और पोर्टफोलियो बाधाओं का उपयोग करता है।

अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब का तीन दिवसीय गुजरात दौरा

अहमदाबाद (ईएमएस) हाल ही में उदयभानु चिब को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया हैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद वह पहली बार गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं इस महीने में 27, 28 और 29 तारीख को वह गुजरात प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और तहसील, जिला और राज्य के अधिकारियों के साथ विस्तारित व्यवसाय में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और आगामी युवा कांग्रेस गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। गुजरात प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ऋतुराज सिंह चुडास्मा ने कहा कि गुजरात में युवाओं की कई समस्याएं हैं आज के युवाओं के पास नौकरी नहीं है और सरकार युवाओं को नशा देकर बर्बाद करने की साजिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब की अध्यक्षता में गुजरात प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे 27 नवंबर को राजकोट में शक्ति सुपर शी, 28 नवंबर को मुंद्रा-कच्छ में नौकरी दो, नशा नहीं कार्यक्रम होगा 29 नवंबर को अहमदाबाद के लॉ गार्डन क्षेत्र के ठाकोरभाई देसाई हॉल में ''नशा नहीं नौकरी दो'' कार्यक्रम होगा। गुजरात प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदित्य सिंह गोहिल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात प्